



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY



भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 20, 1980/ज्येष्ठ 30, 1902

No. 113]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 20, 1980/JYAISTHA 30, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि वह अलग संकालन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(प्रार्थिक कार्य विभाग)

बजट अनुभवग

बजट 1980-81

वित्त मंत्री का भाषण

नई दिल्ली, 18 जून, 1980

पद्र सं. वि०मं० (वी ई ए) य००८०८०८० का० १५ (१)-बी (डी) /८०

(भाग क)

महोदय,

मैं वर्ष 1980-81 का नियमित बजट प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित
हूँ।

2. इस वर्ष मार्च में अंतिम बजट प्रस्तुत करने समय मैंने यह
बताया था कि हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की हालत किन्तु खाली है,
और उसे ठीक करने के लिए राष्ट्र को किनारा भारी काम करना होगा।
पिछले मध्याह्न सर्वत में प्रस्तुत “प्रार्थिक समीक्षा” से मेरे उत्तर विचारों
को पुष्ट होती है, जो मैंने संक्षेप में भार्ता के महीने में व्यक्त किए थे।
“प्रार्थिक समीक्षा” में भारतीय अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान दशा और उसकी
समस्याओं वथा समावनाओं का विस्तृत व्योरा दिया गया है, हमलिए मैं
यहाँ उसके कुछ प्रमुख पहलुओं पर ही प्रकाश डालूँगा ताकि सर्व को
यह मालूम हो सके कि इस सरकार के सामने जो प्रार्थिक समस्याएं हैं।

ये किनती गम्भीर हैं, उन्हें सुलझाने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्य-
वाई की है और प्रागे कौन-कौन से उपाय करने की ज़रूरत है, और
इन उपायों में से कुछ एक के बारे में मैं प्रपने इस भाषण में प्राप्त बताऊँगा।

3. भारतीय अर्थ-व्यवस्था की सबसे अधिक महत्वपूर्ण और चिन्ताजनक
बात यह है कि 1979-80 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में लगभग 3 प्रतिशत
की गिरावट आई। यह गिरावट कृषि उत्पादन में लगभग 10 प्रतिशत
की और ग्रीष्मांगिक उत्पादन में लगभग 1 प्रतिशत की कमी होने के कारण
हुई। कृषि उत्पादन में कमी इसलिए आई क्योंकि वेश के बहुत बड़े
भागों में भयानक सूखा पड़ा। ग्रीष्मांगिक उत्पादन में कमी होने का मुख्य
कारण यह था कि प्राधारभूत डांडे की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई
थी।

4. प्रार्थिक स्थिति की जो महसूस अधिक गम्भीर लुटिया रही उनमें
ने एक बुटि बिजली, कोयला और रेल के उत्पादन से संबंधित थी।
इसमें कोई सन्देह नहीं कि सूखे के कारण पन-बिजली के उत्पादन में

2.2 प्रतिशत की कमी आई। लेकिन जो मुख्य बात हमारे सामने उभर
कर आती है वह यह है कि यिन्हें तीन बारों में तापीय बिजली के
उत्पादन की क्षमता में पर्याप्त बढ़ोतारी होने पर भी उसके उत्पादन में
बृद्धि करके बिजली की बड़ी हुई मांग को पूरा नहीं किया जा सका।
कायने की प्रयोगी पूर्ति और घटिया बवालिटी, मशीनों प्रादि का घटिया
रख-खाल, उत्पक्ष की खराबी जिसके कारण पूर्व-योजना के अनुसार
तथा अन्यथा भी बिजलीबन्दी की प्रवधियाँ बढ़ानी पड़ी और निहृष्ट
प्रबन्ध—में सब ऐसो बातें थीं जिनके कारण तापीय बिजली की क्षमता
का उपयोग घटकर 45 प्रतिशत तक ही रह गया।

5. कार्यपाल की भी यही कहानी है। भारी पूंजी निवेदन के बाबजूद 1979-80 में कोपले और लिंगनाहट का उत्पादन डीक 10.6 करोड़ मैट्रिक टन हुआ जो जारी बर्य पहले प्राप्त स्तर से थोड़ा-पा ही अधिक था। कार्यपाल के उत्पादन में जो कमा हुई उत्पादन कारण यह था कि दामोदर घाटी निपाल के कार्य-निपाल का स्तर अच्छा नहीं रहा और लिंगनाहट तथा बंगाल के कोपला उत्पादक थोड़ों में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं रही। इनके भवावा, रेलवे के यातायात की कठिनाइयों के कारण कार्यपाल प्राप्त स्तर में तापीय विजलीवरों तक नहीं पहुंचाया जा रहा।

6. वर्ष 1979-80 के दौरान प्रारम्भिक टन भार के रूप में रेलवे के राजस्व उत्पादक यातायात में 1978-79 में प्राप्त स्तर से 3.3 प्रतिशत की कमी रही। प्रारम्भिक टन भार के रूप में राजस्व उत्पादक यातायात में रेलवे ने 1976-77 में सर्वोच्च स्तर प्राप्त किया था और तब से उसमें बगवर कमी रही जा रही है। विजली, कोयला और रेलवे —इन तीनों थोड़ों में जो क्षुटियां रही उन्हींने परम्परा एक-दूसरे को बढ़ावा दिया और गढ़ीय अर्थ-व्यवस्था को गंभीर थकि पहुंचाई।

7. आधारभूत ढांचे की इन संभीकृत लिंगियों के कारण हमारा, सीमेंट विजली-मिश्र मराने, एलूमिनियम और अन्य अन्तीह धातुओं तथा सूती बस्तों जैसी प्रमुख बस्तुओं के उत्पादन में कमी प्राप्त की आशंका नहीं रही। जीनो के उत्पादन में भी 28 प्रतिशत की कमी हुई। उत्पादन के थोड़ों में उत्पादन की गतिशीलता का रूप गिरावट आई।

8. ऐसी स्थिति में जब कि समय पूर्व में एकदम कमी आई, कीमतों में तेजी से बढ़ि हो गई। राजकोपालीय वर्ष 1979-80 में कीमतें 20 प्रतिशत बढ़ी। चानी, गुड़, खांडगारी, लेनहन और खाद्य तेजों जैसी कुछ बस्तुओं की कीमतों में खासी बढ़ाव भी बहुत ज्ञादा बढ़ि हुई। उत्पादन के निम्नस्तर के कारण बहुत गी वित्तिभूत और मध्यवर्ती बस्तुओं की कीमतों में भी जगतार बढ़ोत्तरी होने का रुख बना रहा। कच्चे तेज और तेल उत्पादों की कीमतों में बढ़ि होने के प्रत्यक्ष और प्रत्यन्धी प्रसादों के कारण अर्थ-व्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव बढ़े और कोयले तथा इस्पात जैसी शीजों को प्रगतिशील कीमतों में बेच से किए गए समायोजनों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। इसके कारण स्वामीनिय रूप से मट्टेवारी के आसार बढ़ गए और पिछले वर्षों के दौरान सूक्ष्म उत्पादित्र में अन्यथिक विस्तार किए जाने से मट्टा प्रणाली में तकड़ी का बढ़ाव हो जाने के कारण कीमतों की स्थिति और भी नंगी हो गई।

9. इन सभी बातों के कारण जिम एक अन्य थोड़ा में स्थिति लिंगड़ी वह था भूगतान—ज्ञेय का थोक्स। यह मही है कि 1979-80 में विदेशी मुद्रा के भाड़ार में कुल मिलाकर केवल 5.6 करोड़ रुपए की भी कमी हुई किन्तु भूगतान-ज्ञेय पर असर डालने वाली विभिन्न शक्तियों का रुख स्थगित: उनट गया। सूख के रूप में निर्धारित की बढ़ि केवल 8 प्रतिशत के असाधारण रूप जिसका मतलब यह हुआ कि परिमाण के रूप में जायद ही कोई बढ़ि हुई हो क्योंकि 1979-80 में विश्व स्तर पर लगभग 10 प्रतिशत की दर से मुद्रास्काति हुई। दूसरी ओर, आशानों में लगभग 25 प्रतिशत की बढ़ि हुई जिसका मुख्य कारण यह था कि तेल का बिल बढ़ गया था क्योंकि तेल और तेल उत्पादों की कीमतों में भारी बढ़ि हुई थी और उत्पादक जैसी बस्तुओं के आवात पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इसके परिणामस्थल 1979-80 में व्यापार का घाटा 1978-79 के घाटे की तुलना में दुगुना यानी 2232 करोड़ रुपए का था। इसकी बजह से चालू खाने में भी घाटा रहा। बाहर से भेजी जाने वाली रकमों की बढ़ि की दर भी, जिसके कारण अभी कुछ समय पहले अपार का घाटा अधिकैश में बदल गया था, 1979-80 में भीमी पड़ गई।

10. यह असंतोषजनक आर्थिक स्थिति काफी हृद तक पिछली सरकार की नीतियों पर मैं कहूं कि नीतियों के प्रभाव के कारण उत्पन्न हुई। उदाहरणार्थ, जीनो के सम्बन्ध में दुसरों तीसरों नीति के कारण यह क्षेत्र में कमी हुई और जीनो का उत्पादन भी बढ़ गया और पिछले मौसमों

में इससे किए गए जीनो के विभास भेंडारों की उमसे बार-बार जीनो निकास कर बरबाद कर दिया गया और बाद में हन निकासियों का बार-बार नहीं रखा जा सका। यहि बे जीनो के मामते में अधिक उत्तर-व्यायामपूर्ण नीति का अनुसारण करने तो हमें घरेलू उत्पादक के लिए बाहर से जीनो मामते की अवाधिनीय स्थिति का मामता नहीं करना पड़ता।

11. जहां तक आधारभूत ढांचे का संबंध है, कोयला, परिवहन और विजली के तीन क्षेत्रों में समन्वय नीति न होने के कारण कार्य-निपाल उत्पादन मनोरंजनक नहीं रहा। नकदी बढ़ाव वालों अर्थ-व्यवस्था में जाहां बजट में 2700 करोड़ रुपए का भारी घटने हुए उत्पादन की स्थिति में आप उत्पादक की बस्तुओं पर अपेक्षा लग से कर लगाने की नीति हो तो कीमतों में उत्ताल आता स्थानांकित हो जाए। मन्त्री, नियरिं उत्पन्न एवं दूर्वाल पर पर्याप्त बन न दिए जाने के कारण भी यह जाहां हमारे भुगतान-पेय का रुख उलट गया।

12. अब यह जहां जीनो हो गया है कि हालत को और ज्यादा लिंगड़े से रोकने के लिए और अर्थ-व्यवस्था को स्थिरना और विकास के पथ पर अप्रभाव करने के लिए उत्पाद खोजने जाएं। इस तथ्य से कि हमारी सरकार को जनता का विषयाल प्राप्त है और उसमें निर्णय लेने की अमता है, स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन आना चाहिए, हमके अलावा यह भी मही है कि प्रबल जब कि गर्जों के चुनावों में अमारे पर्टी को इन्हें उत्पाद के मायथियां खोना चाहिए है, केन्द्र और राज्यों के बीच अबूत अधिक भयोग करेगा। हमने पहले जो दूरदर्शिता दिखाई थी उसके कारण अब मई 1980 के अन्त में भी हमारे पास 180 लाख मैट्रिक टन खाद्य का भड़ार है। लिंगों मुद्रा भंडार 30 मर्फ़, 1980 का 4890 करोड़ रुपए का था। स्थिति को सुधारने के लिए हम भास्कर तत्वों का मकानापूर्वक उत्पादक किया जाएगा। लेकिन मध्यन यह महसूस करेगा कि हमें जिन्हीं गंभीर और जटिल समस्याएं विगत में मिली हैं उनको जल्दी से सुनामा देना कोई आमान काम नहीं है। किन्तु ये समस्याएं ऐसी हैं जिन पर तकाल ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है, हमलिए हम दूसरंकल्प होकर और जनता के सभी बगैंचों के सहयोग से हमें सुलझाने का प्रयत्न करें।

13. जब से हम सरकार ने मना मंभाली है तब से हमने आर्थिक प्रणाली की चुटियों को ठीक करने के लिए कई कदम उठाए हैं। चूंकि आधारभूत ढांचे को मधी स्थिति में लाने के काम में किसी प्रकार की दौरी बर्बाद नहीं की जा सकती थी इसलिए सरकार ने स्थिति पर बगवर नजर रखने के लिए मेरी अधिकैशा में आधारभूत ढांचे के बारे में एक मंत्रिमंडलीय समिति गठित की। चूंकि विजली की कमी उत्पादन की बढ़ि में बाधा डालती रही है इसलिए समिति ने विजली संबंधी स्थिति को मुद्रात्मने की ओर अबूत ध्यान दिया है। समिति हम बात की सुनिश्चित व्यवस्था आहती है कि नावीय विजली के उत्पादन में कोयले की कमी बाधा न लाने हमलिए उसने यह निर्णय दिया कि नावीय विजलीवरों को कोयले पहुंचाने के लिए प्रायिक बैंगन उत्पाद्य कराएं जाएं। इसके कामस्तर नावीय विजलीवरों को प्रतिविन भेजे जाने वाले कोयले के बैंगनों की संख्या मई 1980 में 3200 हो गई है जबकि जनवरी में यह 2900 थी।

14. ऐल दाना कोयले की बढ़ावी की अनुपूर्ण करने के लिए नटवरी नौदियन फिर में चालू किया गया है और आजाना है कि परिवर्त्तन और विकासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसमें उत्तरोत्तर बढ़ि होगी और वह प्रति मास एक लाख मैट्रिक टन वे लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।

15. कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कई कदमों के फलस्वरूप उनके उत्पादन में प्रतील 1979 की तुलना में, इवेल 1980 में 9.4 लाख मैट्रिक टन और मई 1980 में 10.4 लाख मैट्रिक टन की बढ़ि हुई है।

16. पसन्तों की स्थिति में भी आर्थिकैशनक सुधार हुआ है। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में जाट पर लगने के लिए प्रतीक्षा करने वाले जहांजों की संख्या मई 1980 तक बढ़कर बहुत कम हो गई है। पसन्तों की स्थिति

में सुधार हुआ है जिसका सही निदेशक यह नाम्य है कि प्रत्रिल 1980 से और कलकत्ता भावित बड़े पत्तों पर लगने वाला संकुलन अधिभार (कलेज न सरकारी) हटा दिया गया है।

17. भूक भ्रम्भवर 1979 से मई 1980 तक की अधियोग्य में वर्षा कम हुई जिसमें कहीं गाँजों में सूखे का स्थिति बहावर बनो रही और 23 करोड़ लोग इसमें प्रभावित रहे, इन्हिए बर्तमान सरकार ने कार्रवार संभालते हों तुरंत विशाल रैमाने पर राहत कार्य शुरू कर दिया। इन राज्यों ने यह दूसरे राज्यों को भी केंद्रों द्वारा भेजे गये और सूखा राहत के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई। दस लाख से अधिक निराशें को मूक्त भोजन दिया गया। इसके अलावा, "काम के बढ़ते अनुच्छेद" के विशेष कार्रवाक के अन्वर्ग रोजाना लगभग 65 लाख लोगों को रोकार दिया गया। सरकार ने इस कार्रवाक को भित्तिवार 1980 के अंत तक चालू भरने का निश्चय किया है। नाइट्रोजन और ट्रैक्टों संभेद कृषि में काम भवित वाली वस्तुओं (इनपुट) पर लोट और समानित किसानों को एक फसल वाले सूखा प्रभावित जोड़ी में, जहाँ रखी की कोई कमत्र नहीं उगाई जा सकती, इस समय जो अधिक महायाता दी जाती है वह भी मार्च, 1981 के अंत तक दो जाता रहेगा।

18. सूखे के प्रबन्ध का एक 12 सूखी कार्रवाक निवार करके राज्यों के पास भेजा गया है। इस कार्रवाक में यह बताया गया है कि वे मूलतः किस प्रकार सूखे की स्थिति का सुकान्दा करें और इसके लिए क्या इन्टिकोण लगाना। कूर और दोनों के विरुद्ध बहुत से रियों को काम में लाया जा रहा है और बोर्ड किए गए हूँसों में से काफी अधिक प्रतिशत कुकों में सफलता मिलती है। आशा है, इन कृषियों से सूखा-प्रभावित राज्यों में यीं के पानी की उपलब्धता में स्थायी रूप से सुधार हो सकेगा।

19. पिछले कुछ महीनों के दौरान, सूखा भावित कई कारणों से पैदायित उत्पादों, खास तौर से छीजों का मात्र बढ़ गई। यह समस्या और भी जटिल हो गई जब जनवरी से अग्रिम के कृच्चे तेल (कूदू) पर अधिकतम जारी तेल शोधक कारखानों (निकाफनरी) से जिनके द्वारा सामाजिक प्रतिभास लगभग 3,50,000 मीट्रिक टन पैदानियम उत्पाद तैयार किया जाते हैं, होने वाली पूर्ति (भवार्टी) लगभग पूरी तरह ठप्प हो गई। इस स्थिति का पूरी तरह डटकर मुकाबला किया गया। संबंधित, जनवरी और अप्रैल 1980 के बीच छीजों और मिट्टी के तेल अधिकतम मात्रा में अधिकतम किया गया अर्थात् 6.2 लाख मीट्रिक टन मिट्टी का तेल और 11 लाख लाख मीट्रिक टन छीजों बाहर से मार्गदार गया जबकि जनवरी-अप्रैल 1979 से अग्रिमत मिट्टी के तेल और छीजों की मात्रा अग्रम: 4.7 लाख और 4.8 लाख मीट्रिक टन थी। हमारे सभी उपलब्ध साधनों के द्वारा हन वस्तुओं की आवाजाही में नेत्रों लाई गई। इसके फलस्वरूप 1979 के पद्धतिगत महीनों की तुलना में इनकी पूर्ति के ब्लर्म में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई और छीजों की कमी रहने से रखों के उत्पादन पर जो प्रतिक्रिया पड़ता वह नहीं पड़ा।

20. जहाँ तक कीमतों का संबंध है, सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया है। आवाज तेलों के मामले में सरकार ने पर्याप्त मात्रा में इनका आयात ही नहीं किया बल्कि यह भी व्यवस्था की है कि अग्राम किए गए इन तेलों का काफी बड़ा भाग सीधे उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो। उम्मीद है कि लगभग 3 लाख मीट्रिक टन आग्रिम तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली और महाकारी समितियों के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं को उपलब्ध होगा। भीनी के मामले में, सरकार ने इस्तव्यमध्ये हुई बोहरों कीमत प्रणाली को सक्रिय बना दिया है।

21. गर्भाव में गर्भाव व्यक्ति के विकास के लिए हमारी नीति में जो और दिया गया है उसके प्रत्युष बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि परिवर्तित प्राथमिकता प्राप्त लंबे को दिए जाने वाले अंग को काफी बड़ा भाग पुनर्जीवित किया जा रहे 20-सूखी अधिक कार्रवाक

के सुधारनुभौतियों को प्राप्त हो। अपांस्तरीय विकास की गतिविधियों और बैंकों के अंग कार्रवाकों के बीच की कहीं को और मजबूत करने के लिए बैंकों से कहा गया है कि वे इस वर्ष के अंत तक उन सभी अमेरिकी मुद्रायांमध्ये (ब्लाक हैडब्ल्यूटर्स) में प्रपनी शाखाएँ खोल दें जहाँ इस समय बैंक कायासिव नहीं है।

22. सम्मानित सरस्य उम महत्वपूर्ण भूमिका में भर्ती भासि परिवर्तित है जो हमारे नियतों ने हमारे विकास कार्यों से निराई है। इसनीने कई वर्षों से सरकार नियति सरदार को सभी प्रकार की शुरूआतों और पूरा-पूरा प्रोटोकॉल देने की कोशिश करती रही है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जो उन्नीस वर्षों तक जारी रहा है, नियति संबंधित के लिए नियंत्रण वित्त और अंग का प्रबंधन करना आधिकारिक जटिल होता जा रहा है। इसनीएक एसी विशिष्ट संस्था की जरूरत है जो नियति अंग के सभी पहलुओं के लिए एक केंद्र वित्त बने और जो नियतिक समूदाय की आधारिकताओं पर एकाग्र होकर ध्यान दे। नदनुसार सरकार ने हमारे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वित्त व्यवस्था में सहायता देने के लिए एक नियति-प्रायत बैंक स्थापित करने का निश्चय किया है। हमें प्राणा है कि यह विशिष्ट संस्था हमारे नियति संबंधित कार्यों को बांधिन बदावा देंगी।

23. इस समय अर्थव्यवस्था के सभने जो समस्याएँ हैं उनको देखते हुए जो काम किए जाने हैं, वे काफी स्पष्ट हैं। चूंकि अर्थव्यवस्था में स्फीति-कारी संभावनाएँ बहुत अधिक हैं इसलिए हमारी नीति का मुख्य उद्देश्य कीमतों में स्थिरता लाना होगा। समग्र पूर्ति में वृद्धि करके समग्र मात्रा में कुछ कमों करके ही इस कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसनीएहमारा हरादा है कि इस आधारभूत ढांचे के कार्य में सुधार करने के अपने प्रयत्नों को जारी रखें और जहाँ कहीं आधारिक हो पूर्जी निवेश करके उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ावा दें। हमारे, जो इस बात पर दिया जाएगा कि विद्यमान अमना का अधिक कार्रवार छग में उपयोग किया जाए, अमना बड़ानों के प्रयत्नों में कोई दोल न दी जाए, और इस्तान, सीमेंट, एल्यूमिनियम, तथा उत्करक जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाई जाए। इसमें एक भाष्य उत्पादन और रोजगार, अवान की ज़रूरत कम होगी और राजस्व का लाभ होगा।

24. मांग प्रबन्ध के संबंध में, हमें बैंक अंग के विस्तार को उत्पादक और प्राथमिकता प्राप्त प्रयोगों के साथ जोड़ने की नीति का अनुसरण करना होगा और स्ट्रेटजीजों के लिए धनराशि का इस्तेमाल को रोकना होगा। हमें एक ऐसी व्याज दर नीति का भी अनुसरण करना होगा जो उत्पादक कार्यकलाप को अति पर्याप्त विनाकारी दरवाजों को कम करने में सहायता मिल दें। इसी के साथ ही सुनाकाखोरों और जमानों के विस्तर जो कि अर्थिकता हित के लिए बर्तमान कमियों का फायदा उठाना चाहते हैं, कठोर कार्रवाई करनी होगी। नक्सी को नक्सर करने के जरूरी प्राप्ति छलमाधक (मम्पति समपद्धरण) अधिनियम तथा अन्य उपायों के जरिये रोकना होगा।

25. भूक मुद्राप्रणाली में नक्दी का बहुत बहुल्य हो गया है इसलिए बैंकों के घाटे की 1979-80 के स्तर पर बहुत नीचे रखकर मध्य उपलब्धिक बैंकों को न्यूनतम स्तर पर सीमित रखने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए एसी राजकोर्पोरेशन नीति की ज़रूरत होगी जो अर्थ और धनावास्थक व्याप्ति को कम करें, साथीनों को अधिकतम व्यवस्था की उत्पादन अमना बड़ानों में लगाए, भोजना कर प्रणाली की राजस्व उपार्जन की अमता को अधिक से अधिक बढ़ाए।

26. हमारे भ्रातान-सेव्य की बिगड़ी हुई हलात को देखने हुए हम नियति संबंधित के कार्य पर विश्वाले तीन वर्षों की अवैधता कहीं की ज्यादा जोर देना होगा। साथ ही, साथ तेलों, इस्तान, सीमेंट, उत्करक, तेल और लेन उत्पाद जैसी वस्तुओं के मामले में देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए और भ्राता संस्करण नीति के माध्यम से आयातों की बढ़ि को नियन्त्रण स्तर पर रखना होगा।

27. सरकार ऐसी नीतियों का भी अनुसरण करना चाहती है जिसमें प्रथमवस्था में बचत और निवेश को बढ़ावा दिया जाए। 1971 से, लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक एककों को दो जाने वाली वित्तीय सहायता से संबंधित करारों में एक संपरिवर्तनीयता खण्ड रखा जा रहा है। उद्योग भेत्र द्वारा बास-बाबर यह अन्यावेदन दिया जाना रहा है कि संपरिवर्तनीयता अप्प की कठोरताओं के कारण पूँजी निवेश में रकावट आ रही है सरकार ने साधारी पूर्वक इस मामले पर विचार किया है और यह निर्णय किया है कि करारों में संपरिवर्तनीयता खण्ड शामिल किए जाने के लिए नीति संबंधी मार्ग-निर्देशों को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया जाए।—

(क) संपरिवर्तनीयता खण्ड के अनिवार्य समावेश की गारं इन समय-वित्तीय 50 लाख रुपए की बजाय, भविष्य में 1 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता के संबंध में ही लागू होगी।

(ख) वित्तीय संस्थाओं को एतत्प्रकार संपरिवर्तन सबंधी विकल्पाधिकार का प्रयोग इन प्रकार करना चाहिए जिससे कि वे किसी भी गृहीत की कोई बेयर पूँजी के 40 प्रतिशत से अधिक शेयर न ले। किन्तु उन्होंने की वापसी अद्यावधि में बाबाबर चूक किए जाने के मामले में या सहायता प्राप्त कर्त्तव्यी के कुप्रबन्ध के मामले में अधिकारी समाज के लिए ग्रामवस्थक सेवाओं या वन्नुमांक का उत्पादन करने वाली किसी कंपनी की आधिकारिक इकाई के सभातात वह रुपए पर, वित्तीय संस्थाएं सरकार की सहमति से, अपने संपरिवर्तन संबंधी विकल्पाधिकार का प्रयोग इन प्रकार कर सकती है जिससे कि उनकी बेयर धारिता 5 प्रतिशत तक या उससे ऊपर जा सकती हो।

(ग) जूद, सूतों वस्त्र, सीमेंट, चीनों और कानिपय इंजीनियरों उद्योगों के प्रायुनिकीकरण के लिए इन समय जो उदार आण योजनाएं चल रही हैं उनके अन्तर्गत किलहाल कोई संपरिवर्तनीयता खण्ड शामिल नहीं किया जा रहा है। यह छूट अब अन्य सभी प्रकार के उद्योगों के आयुनिकीकरण और रुपण एककों के पुनर्व्यवस्थाएँ के लिए वा जाने वाली सहायता के मामले में भी दी जा रही है।

सरकार की आशा है कि इन नीति विषयक परिवर्तनों से मौजूदा अड्डने दूर ही जायेंगी और उद्योग के प्रायुनिकीकरण को और उसमें नए पूँजी-निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

1980-81 की आयोजना और बजट अनुमान

28. आर्थिक प्रबन्ध का तात्कालिक समस्याओं में व्यस्त रहते हुए भी हमें इस बात को नेजर रखना नहीं कर देना चाहिए कि प्रथमवस्था के विकास की क्षमता का निर्माण मध्यम काल में ही करना चाहती है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो अत्यकालिक कटिनाईयां बढ़ती ही जल्दी जाएंगी। पुनर्गठित योजना आयोग उस समय नए कार्यक्रम और प्राथमिकताएं प्रस्तुत करेगा। जब इस वर्ष के भ्रंत तक आयोजना तैयार कर ली जाएगी। लेकिन इसी बीच वर्ष 1980-81 के लिए आयोजना तैयार कर ली गई है जिसे बाद में छठी आयोजना में समाविष्ट कर दिया जाएगा। आयोजना का मोटा उद्देश्य 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की घोषकालीन ऊंची वृद्धि दर प्राप्त करना होगा।

29. 1980-81 की वार्षिक आयोजना का उद्देश्य प्रथमवस्था को पुनर्जीवित करना और उसे पुर्ववत् स्वस्थ बनाना है तथा विकास और रोजगार के प्रबन्धर पैदा करने की गति को बेज़ करना है। हालांकि पिछली सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताएं हमें स्वीकार्द नहीं हैं फिर भी हमने यह माना है कि पहले से बड़ी आ रही परियोजनाओं के लिए पूरी-पूरी व्यवस्था की जाए। इस विकास से समायोजन क्षमता की परिवर्धन में रहते हुए हमने आयोजनागत व्यवस्थाओं में परिवर्तन किए हैं और नये कार्यक्रमों के लिए इस प्रकार व्यवस्था की है ताकि आयोजना को बांधित दिया जा सके।

30. नए योजना आयोग ने आयोजनागत कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं की तुरंत समीक्षा की है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता ही रही है कि इस समीक्षा को वृद्धिगत रखते हुए केन्द्र की 1980-81 की वार्षिक आयोजना के परिवर्य को बढ़ावकर 7340 करोड़ रुपए किया जा रहा है, इस प्रकार प्रत्यक्षित बजट में व्यवस्थित परिवर्य में 767 करोड़ रुपए की वृद्धि की जा रही है। और यदि पिछले वर्ष के मूल परिवर्य से इसकी तुलना की जाए तो यह उससे 14.5 प्रतिशत अधिक है। इसकी वित्तीयवस्था के लिए बजट में 5322 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है और 2018 करोड़ रुपए सरकारी भवन के उपकरणों के आलंगिक और अन्य साधनों से जटाया जा रहा है। राज्यों की आयोजनाओं, संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं, उत्तर पूर्वी परिषद की योजनाओं, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और ईंटी विपक्षीयों से केंद्रीय सहायता देने के लिए 3094 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उनके अपने साधनों महित उनका आयोजन। परिवर्य 7253 करोड़ रुपए का होगा जबकि 1979-80 में यह परिवर्य 6099 करोड़ रुपए का था। केन्द्र, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी परिषद की योजनाओं आदि का समस्त आयोजना परिवर्य कुल मिलाकर 1980-81 में 14,593 करोड़ रुपए का होगा, जबकि 1979-80 में यह 12,511 करोड़ रुपए का था; इस प्रकार उसमें 16.6 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

31. इस सरकार का यह पक्ष का विश्वास है कि आधिक विकास की गति को तभी तेज़ किया जा सकता है और इसके मुफ्कां का व्यापक रूप से बढ़ावारा तभी किया जा सकता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के प्रबन्धरों में विशेष वृद्धि की जाए। हमारी जनता के बहुसंख्यक लोगों के लिए तब तक विकास का कोई मतलब नहीं होगा जब तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोग संतोषजनक उत्पादक कार्य के जरिये अपनी जीविका नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमने नई आयोजना के एक अधिक्षण अंग के रूप में एक विशाल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम बलाने का निष्पत्ति किया है जो एक ऐसी नीति पर आधारित है जिसका उद्देश्य स्वावलंबन के प्रबन्धरों और उपलब्ध स्थानीय माध्यनों के इष्टतम उपयोग में समर्जनस्थापित करना होगा। ऐसे कार्यक्रम से ग्रामीण प्रथमवस्था में फिर में प्राण फूकने और जन-जीवन के लिए अनिवार्य आधारभूत सुविधाओं का विकास करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

32. इस संबंध में “काम के बदले प्रनाल” कार्यक्रम को भी, जिसे हमने 1977 में शुरू किया था एक महत्वपूर्ण भूमिका अद्या करनी है। लेकिन पिछले दो वर्षों में इस कार्यक्रम में कठु बनियादी कमजोरियां विद्याई तो हैं। बहुत से मामलों में, ऐसी परियोजनाओं की एक तात्कालिक बनाने की कोई कौशिक नहीं की गई जो न केवल स्थानीय जलस्रों को ही प्रारंभ करेगी बर्तक जो समग्र नाट्रीय प्राथमिकताओं में भी ईक से समाविष्ट हो सकेंगी। आद्यान के वार्षिक आवंटन के लिए भी कोई पक्षका संकेत नहीं दिया गया। इस प्रकार इस कार्यक्रम को बस्तुतः एक तर्वर्य आधार पर ही बलाया जा रहा था। राज्य भरकारों द्वारा उनको आवंटित आद्यान की सहायता से जाना जाने वाले निर्माण कार्यक्रम के नकादी अंश की वित्तीयवस्था के लिए भी कोई प्रबन्ध नहीं किए गए थे। इसका परिसाम यह हूँसा कि ये ऐसे निर्माण कार्य हाथ में नहीं ले सके जिनसे टिकाऊ परिसम्पत्तियों का निर्माण होता और संबंध क्षेत्रों की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती।

33. नए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में, राज्यों को आद्यान के रूप में ही नहीं बर्तक नकादी के रूप में भी सहायता मिलेगी जिससे वे ऐसे निर्माण कार्य हाथ में ले सकेंगे जो आसान रूप से उत्पादक होंगे और स्थायी लाभ देंगे। सबन में जो बजट अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं उनमें इस कार्यक्रम के लिए 1980-81 में 340 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अनुमान है कि यदि यह कार्यक्रम ठीक तरह से कार्यान्वित किया गया तो इससे 85 से 90 करोड़ अधिक रिंगों का अतिरिक्त रोजगार पैदा होगा। इस योजना के लिए भी गई व्यवस्था का कठु भाग सामाजिक बनपालन, जनाने की लकड़ी के वृक्षारोपण, ग्रामीण सामुदायिक आयास और जल-पूर्ति

तथा पोषाहार, जैसे उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के लिए विषिष्ट रूप से अधिकारित किया गया है। पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्य के लिए 10 करोड़ रुपया की व्यवस्था की गई है।

34. आधिक विकास की प्रक्रिया तक तक अधूरी रहेगी जब तक कि इस विकास के लाभ समाज के मध्यसे कमज़ोर वर्गों तक नहीं पहुंचें। इसलिए अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आधिक वृश्चिक का मुद्दाहर करना हमारी विकास नीति का प्रमुख तत्व होना चाहिए। अनुसूचित जातियों के लिए व्यापक विशेष संबंधक आयोजनाएं लेयार करनी होती जिनका उद्देश्य प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में सभी संगत क्षेत्रों में परिव्यय नियन्त्रित करना है। इन परिव्ययों का उपयोग अनुसूचित जाति के परिवारों को प्रपने रहन-सहन की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए संगत कौशल और आय पैदा करने वाली परिस्थितियों प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इस प्रयोजन से राज्यों को 100 करोड़ रुपए की विशेष केंद्रीय सहायता देने की व्यवस्था करके इस बजट में एक नई शुद्धारात्र की गई है; यह राशि विनीय संस्थाओं महिल अन्य साधनों से और अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए ब्रेक तत्व का कार्य करेगी। इसके जरिए प्राथिकारी अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आधिक वृश्चिक का मुद्दाहर करना अनुसूचित जातियों का प्रमुख राज्यकार्यम में उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

35. जनजातीय लोगों और जनजातीय उप-आयोजना के अन्तर्गत जाने वाले क्षेत्रों के विकास के लिए 70 करोड़ रुपय की केंद्रीय सहायता की व्यवस्था की गई है। 10,000 की आवादी वाले ऐसे कुछ और इनकों का पता लगाया जाएगा जहाँ कम से कम 50 प्रतिशत नियावी जनजाति के हों और इस प्रकार अटारह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की लगभग 75 प्रतिशत जनजातीय आवादी को जनजातीय उप-आयोजना के अन्तर्गत लाया जाएगा। जनजातीय परिवारों को लाभ पहुंचा मकान वाले कुछ चुने हुए कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया जाएगा।

36. बीस मूली आधिक कार्यक्रम के अंग के रूप में, भूमिहीन और कमज़ोर वर्गों के लिए घर बनाने के बास्ते जमीन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से 1980-81 की वाधिक आयोजना में लगभग 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। भौतिक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित, भूमिहीन मजदूरों के लिए ग्रामीण आवास-एवं-झोपड़ी निर्माण की योजना में और बनाने के लिए जमीन की ही नहीं बल्कि झोपड़िया बनाने के लिए सहायता देने की भी व्यवस्था है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक आवास परियोजनाएं शामिल होती हैं, इस व्यवस्था की अनुपूर्ति की जाएगी। उम्मीद है कि इस योजना के अन्तर्गत लगभग 8 साथ भूमिहीन परिवारों का आश पहुंचेगा।

37. चूंकि भारत गांधे में रहता है और इसकी लगभग 70 प्रतिशत आवादी कृषि से प्रपने जीविका चलाती है, इसलिए देश की समृद्धि कृषि के आधुनिकीकरण पर निर्भर करती है। 1979-80 का वर्ष इस निष्ठर तथ्य की याद दिलाता कि भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि का कार्यनिव्यादन कितना महत्वपूर्ण है। चालू वर्ष में कृषि और ग्रामीण विकास के आयोजना परिव्यय को 1979-80 के 1811 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2247 करोड़ रुपए किया जा रहा है। इस राशि में केंद्रीय आयोजना के अन्तर्गत ये व्यवस्थाएं शामिल हैं एंटे किसानों की विकास एंजेंसी सूखा आवश्यकता कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि के लिए 158 करोड़ रुपए; अन्तर्देशीय और समृद्धि मछली उत्पादन क्षमता के बेहतर उपयोग के लिए 32 करोड़ रुपए; भरपुर दूष II परियोजना के लिए 54 करोड़ रुपए; बेहतर बीजों, बेहतर मस्त-वैज्ञानिक प्रणालियों बेहतर जल प्रबंध और उर्वरको तथा अन्य उपयोगी बस्तुओं के बेहतर इस्तेमाल के जरिये कृषि की उत्पादकता में मुद्दाहर लाने के लिए उद्दिष्ट कृषि अनुसंधान और शिक्षा की योजनाओं के लिए 59 करोड़ रुपए; और 120 लाख मेंट्रिक टन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेलहानों के उत्पादन की बढ़ि

38. तेल और तेल उत्पादों की अन्तर्देशीय कीमतों के वर्षमान संतरों ने अन्य ईधनों के महत्व को उत्तराधार कर दिया है। ऐसे एक ईधन की व्यवस्था करने के लिए जंगल महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। चूंकि भारत में लोगों ने ईधन की ओर में जंगलों का बहुत नेजी से सफाया किया है, इसलिए यह प्राथमिक है कि जंगलों के विकास में तस्कालत आधार पर लोगों का भव्योग प्राप्त किया जाए। गांवों में सामाजिक वनपालन से लोगों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं साथ ही उनको अतिरिक्त रोजगार भी मिलेगा। ईधन और चारोंपैदा करने के काम का अन्तर्मात्र आवश्यकता कार्यक्रम का अंग बनाने का प्रस्ताव है और इसे गण्डीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

39. उत्पादन में घट-बढ़ को दूर करने के लिए और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें सिवाई के क्षेत्र को बढ़ाते जाने के कार्य पर बाबाबर और देते रहता होगा। अन्तः 1980-81 में बाढ़ नियंत्रण सहित बढ़ों और मध्यम सिवाई परियोजनाओं के लिए परिव्यय को, पिछले वर्ष के 1258 करोड़ रुपए से बढ़ाकर, 1380 करोड़ रुपए किया जा रहा है। मिवाई के कार्यक्रम पर परिषेप द्वारा न दिया जाना रहेगा और इस प्रयोजन के लिए 266 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के प्रलावा, इसी प्रयोजन के लिए कृषि पुनर्विन और विकास निगम से भी बढ़ों माला में विनीय सहायता मिलेगी। इस सम्पूर्ण व्यवस्था से, आशा है, 25 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिवाई की क्षमता का निर्माण होगा।

40. ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के स्तर को सुधारने के लिए स्वच्छ और निरापद पेय जल एक आवश्यक बल्ट है। 1980-81 की केन्द्रीय आयोजना में, 1979-80 के 80 करोड़ रुपए के मुकाबले में, 100 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। राज्यों का ग्रामीण जनाओं में की गई व्यवस्थाओं को शामिल करने पर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए कुल 294 करोड़ रुपए उपलब्ध होंगे। आशा की जाएँ है कि चालू वर्ष के अन्त तक, समस्याग्रस्त माने गए 35,000 अतिरिक्त गंवारों के लिए सुरक्षित जलपूर्ति की व्यवस्था कर दी जाएगी। परिव्यय के एक प्रमुख का उपयोग सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कूप और, करने के उद्देश्य से राज्यों को आज देने के लिए किया जाएगा। नई जलपूर्ति योजनाएं हाथ में लेने के लिए भीर पहले से हाथ में लो गई योजनाओं को पूरा करने के लिए सूखा प्रभावित राज्यों को आसू वर्ष में लगभग 40 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आर्द्धांतिक की गई है।

41. बादी, गाम और नश्वर उत्तरों के क्षेत्र में, सूखी के बाद, सबसे प्रधिक रोजगार प्रदान करने की संभावित क्षमता है। इस क्षेत्र के लिए चालू वर्ष में 150 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है और इस वर्ष इस क्षेत्र में 146 करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन का अनुमान है। सबन की बाद होता कि इस संबंध में 20 सूखों आर्थिक कार्यक्रम में हाथ-करण क्षेत्र के विकास पर ज्ञात तौर से जारी दिया गया है। इस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए, हम राष्ट्रीय स्तर पर एक आधुकरण विकास निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं ताकि हाथकरण उद्योगों के लिए एक साथ विपणन और विकास संबंधी सहायता की व्यवस्था की जा सके। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में, जो अपने बड़िया हाथकरण कफ़ड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, एक हाथकरण प्रोटोटाइपिकी संस्थान की स्थापना करने के लिए भी व्यवस्था की गई है।

42. विज्ञी के क्षेत्र के लिए की जाने वाली व्यवस्था में 11 प्रतिशत से भी अधिक की बढ़ि कर दी गई है, अर्थात् इस वर्ष, 1979-80 में की गई 2466 करोड़ रुपए की व्यवस्था के मुकाबले 2745 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वेग के विभिन्न भागों में उच्च तापीय विज्ञी भरों के काम में तेजी लाई जा रही है। वर्ष 1980-81 में गांवों में विज्ञी लगाने के कार्यक्रम के लिए कुल 285 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। वर्ष 1980-81 में 4 लाख पर्सनेटों की विज्ञी वेजे और 25,000 गांवों में विज्ञी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

43. इसी प्रकार, कोयले (लिंगनाइट सहित) का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1980-81 में 473 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है जबकि पिछले वर्ष इस काम के लिए 364 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। इस रकम में नेबेली लिंगनाइट निगम के लिए की गई 92 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है। इस व्यवस्था में से प्रधिकांश राशि दूसरी बार परियोजना के लिए है जिसके प्रभावतान प्रति वर्ष 45 लाख मैट्रिक टन कोयले का उत्पादन होगा और 620 मंसावाट की उत्पादन क्षमता का दूसरा तारीख लिजली घर लगाया जाएगा। आलू वर्ष में 1135 लाख मैट्रिक टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है जबकि 1979-80 में बास्टिक उत्पादन 1060 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य था।

44. तेल की बढ़नी हुई कोमर्तों के कारण भूगतान शेष पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए तेल के हमारे अपने साधनों का तस्कान विकास करने की आवश्यकता के बारे में दो महं नहीं हो सकते। पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए वर्ष 1980-81 की आयोजना में 837 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जो पिछले वर्ष के परिव्यय से 215 करोड़ रुपए अधिक है। इस परिव्यय में से बजट में केवल 99 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह परिव्यय आमतौर पर विकास के तीसरे चरण की सुविधाओं को पूरा करने और चौथे चरण के संबंध में अधिम कार्रवाई करने के लिए है ताकि वार्षिक उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 120 लाख मैट्रिक टन किया जा सके। इसमें सातवां बेमिन गैस फील्ड के विकास और नई उर्वरक परियोजनाओं तक नीम पाइप लाइन लिजाने का लक्ष्य भी शामिल है। पूरी ज्ञेय में हाइड्रो कार्बन मिलने की ऊंची संभावनाओं की देखते हुए उम क्षेत्र में नट पर अन्वेषणात्मक खुदाई (ड्रिलिंग) का काम नेज किया जाएगा।

45. वर्ष 1980-81 की केन्द्रीय आयोजना में रसायनों तथा उर्वरकों के परिव्यय को बढ़ाकर 319 करोड़ रुपए किया जा रहा है ताकि महाराष्ट्र और ग्रामांश में सैम पर प्राप्तिगत नए उर्वरक कारखानों के लिए समर्चित व्यवस्था की जा सके। इसके अन्तर्गत, महाराष्ट्र क्षेत्र की उर्वरक परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है।

46. आलू वर्ष की केन्द्रीय आयोजना में इस्पात क्षेत्र के लिए भी पिछले वर्ष के 600 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में 803 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस परिव्यय में शोकारों इस्पात कारखाने की वार्षिक क्षमता को 40 लाख मैट्रिक टन तक बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपए की और भिलाई इस्पात कारखाने के संबंध में ऐसे ही विस्तार के लिए 190 करोड़ रुपए की रकम शामिल है। भेलम परियोजना का काम प्रोक्षित गति से बढ़ावा रहेगा जिसके लिए 57 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। नए विशाखापत्तनम् इस्पात कारखाने के लिए 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था के माथ एक अत्यधी खासी शुहदारी की जाएगी। आलू वर्ष के लिए विक्री योग्य इस्पात का लक्ष्य 87.6 लाख मैट्रिक टन रखा गया है जबकि 1979-80 में 72.2 लाख मैट्रिक टन के उत्पादन की आशा थी।

47. खान क्षेत्र के लिए 1980-81 में 130 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इस व्यवस्था में नई पूरी तरहरी ड्रेल्यूसेनियर परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपए, मल्वंज खण्ड ताबा परियोजना के लिए 28 करोड़ रुपए तथा भारतीय भू-गर्भ सर्वेशं और ब्रह्मनगर अन्वेषण निगम के कार्यकालाप को नेज करने के लिए 19 करोड़ रुपए की रकम शामिल है।

48. भारत हैबी इंसैक्यूलन्म लिमिटेड की आलू योजनाओं तथा हरिद्वार में बड़े आकार के टर्बो जनरेटरों के उत्पादन और तिहांची में बायलर निर्माण क्षमता के विस्तार के लिए 64 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

49. चूंकि भारती हाल में विकास कार्य में जाधा के रूप में पन्नों पर भीड़-भाड़ की बड़ी चर्चा रही है इसलिए भीड़ और लॉटे पन्नों का विकास करने के लिए 102 करोड़ रुपए भी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन 1980-81 के बजट में इस प्रयोजन के लिए केवल 60 करोड़ रुपए की ही व्यवस्था की गई है क्योंकि योग्य वर्ष की व्यवस्था पतल न्यासों द्वारा

स्वयं प्रपते आन्तरिक साधनों से की जाएगी। केंटेनर यातायात की प्रत्याशित वृद्धि से निपटने के लिए बहुई, मात्रात्र और कोरीक में संवर्तन दर्शाई जा रही है। कोरीन पन्न के समर्चित विकास के लिए शुद्धपान की जा जानी चाही है।

50. डाक-नार विभाग के लिए 1980-81 का आयोजना परिव्यवध 415 करोड़ रुपए रखा गया है। इस वर्ष 1.75 लाख लाइनों की अनियिक स्थितिगत क्षमता, 1.7 डायरेक्ट एक्सेंज लाइनों और भ्रम्य सुविधाओं के लिए व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण, पिछड़े और पहुँची इलाकों में आक घरों की संख्या बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। जनजातीय लोकों में तर और टेलीफोन की सुविधाओं की व्यवस्था करने के मानकों की ओर उदार बना दिया गया है ताकि 10 किलोमीटर के बेरे के प्रदूर प्रदूर वाले 2500 की आबादी घरों गांवों के समूह को भी नार और टेलीफोन की सुविधाएँ पहुँचाई जा सके। स्थितिगत उपकरणों की निर्माण क्षमता के विस्तार के लिए भी व्यवस्था की गई है।

51. पिछले तीन वर्षों में परिवार नियोजन के काम को भारी धब्बा पहुँचा है। यदि लोगों के रहन-महन की परिविधियों को सुधारा दूरेश्य है तो इस कार्यक्रम में फिर में नई जान डाकना नई वंचवर्तीय आयोजना का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 1980-81 में 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था को जा रही है। इसमें से 140 करोड़ रुपए परिवार कल्याण के लिए होंगे। परिवार कल्याण कार्यक्रम में लोगों को लॉटे परिवार की बांडीयता के बारे में शिक्षण करने और पर्यावरण स्तर पर आवश्यक तकनीकों भेजाओं की व्यवस्था करने पर बन दिया जाएगा। ग्रामीण लोगों में बहनर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करने की दृष्टि जिया जाएगा।

52. वैष्ठ करोड़ को जनसंख्या बोर्ड गणीय सभाज के विकास की समस्याएँ निपत्त्य ही बहुत बड़ी होगी। एक उचित समय के अन्दर अन्वर इन समस्याओं को हल करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्तियों का उपयोग करना बहुत जरूरी है। सीमागत से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। क्योंकि भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी विजेता काफी मंद्या में है और पिछले ही साल वर्षों में लॉटे विज्ञान की शक्तियों के विकास के संबंध में भारत में एक बहुत व्यापक संस्थागत प्राधारमूल ढांचा तैयार हो गया है। यद्यपि हमारी वैज्ञानिक संस्थागत विज्ञान के थेट्र के विस्तार में स्वास्थ्यक मिल हो सकती है लेकिन उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में भी विज्ञान पर प्राधारित प्रौद्योगिकी ही काम आ सकती है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 1980-81 की केन्द्रीय आयोजना में 116 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

53. अब मैं कुछ उन परिवर्तनों का संक्षेप में उल्लेख करूँगा जो आयोजना भिन्न व्यय में किए गए हैं। रक्षा व्यय के लिए 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था को गई है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय बजट में की गई व्यवस्था से 300 करोड़ रुपए अधिक है। नियांन के लिए दो और अधिक प्रदूर प्रदूर स्वयंसेवकों की व्यवस्था की गति 330 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 355 करोड़ रुपए कर दी गई है।

54. अलं घबन मंथर्हों में हांते वालों प्रश्नाशित वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकारों के हिस्से के रूप में उन्हें दिया जाने वाला अर्थों की राज्य अन्तर्राष्ट्रीय बजट के 650 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 715 करोड़ रुपए कर दी गई है। अंतों में काम आने वाले वालों वस्तुओं के लिए राज्य सरकारों की दिया जाने वाले अल्पकालिक अर्थों की रकम में भी 50 करोड़ रुपए की वृद्धि की जा रही है। इसके प्रश्नावाक केन्द्रीय सरकार के कर्मजारियों के लिए प्रश्नावाक महर्गाई भूमा, परमाणु विज्ञानघरों के लिए भारी पानी वालों की अवाद आदि जैवी अन्तर्वर्ष बचनबद्धताओं को पुरा करने के लिए भी अतिरिक्त व्यवस्था करना जहरी ही गया है। लेकिन उत्पादकों पर वी जाने वाली प्राथिक सहायता में कटौती कर दिए जाने से प्रश्नावाक-भिन्न व्यय की वृद्धियाँ कुछ हद तक प्रतिसंतुलित हो जाएंगी।

55. सतीश्वान में सरकार द्वारा निशुक्ष कानूनी सहायता देने की परिवर्तना को गई है ताकि आधिक या अन्य अधिकारियों के कारण कभी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसर में विचित्र न होना पड़े। कानूनी मद्दतियों की संवादिता के विषय में नियायीण पी० एन० भवती की अधिकारी में स्थापित विधिक सहायता समिति द्वारा विचार किया गया है; इस समिति की दिग्निक 31 अगस्त, 1977 की गिरिंद्र सगद के सम्मुख प्रस्तुत कर दी गई है। कई राज्य कानूनी सहायता संबंधी कार्यविधि चलाने की विधा में प्रवर्तनाएँ हैं। इस नियंत्रण में विभिन्न पदनामों पर विचार-विधियों करने के बाद इन योजनाओं का समन्वय करने और केन्द्र स्वर पर उपर्युक्त योजनाएँ शुरू करने का प्रयत्नाव है। कानूनी सहायता संबंधी योजनाओं का मार्गदर्शन करने विशेष उपर्युक्त समिति में आने के लिए उत्तम व्यायाम के एक व्यायामिक की अधिकारी सहायता में एक समिति का गठन किया जा रहा है। वर्ष 1980-81 के बजट में इस प्रयोजन के लिए व्यवस्था की गई है।

56. उपर्युक्त तथा कुछ अन्य परिवर्तनों के प्रभाव को हिसाब में लेने के बाद प्रबंध कुल मिलाकर 13051 करोड़ रुपए के भायोजना मित्र व्यवस्था का अनुमान लगाया गया है जबकि अन्तर्रिम बजट में 12822 करोड़ रुपए का अनुमान था।

57. जहां तक वाले वर्ष की प्राप्तियों का संबंध है करारातन के वर्तमान स्तरों के अनुमान नियम-कर से अन्तर्रिम बजट में दिखाई गई राशि की तुलना में 11 करोड़ रुपए की अधिक प्राप्ति का अनुमान है; यह वृद्धि मुख्य रूप से 1979-80 के संग्रह की वान्यविधि प्रवृत्तियों पर प्राप्त है। वर्ष के दौरान आयात और उत्पादन के अनुमानित स्तरों के संबंध में उपलब्ध सबसे हाल के आकड़ों के आधार पर अन्तर्रिम बजट की तुलना में सीमा-शुल्कों से 40 करोड़ रुपए और संघ उत्पाद-शुल्कों से 108 करोड़ रुपए की अधिक प्राप्ति होने का अनुमान है। लेकिन हाल में सरकार द्वारा उपर्युक्तों पर से सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क हटा लेने के लिये के परिणामस्वरूप उपर्युक्त अधिक प्राप्तियां बहुत कुछ घटाव हो जाएंगी। करों में राज्यों के हिस्से को हिसाब में लेने के बाद करारातन की वर्तमान दरों पर अब 8723 करोड़ रुपए का निवल कर राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है जबकि अन्तर्रिम बजट में 8725 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था।

58. सबसे हाल के उपलब्ध संकेतों के आधार पर 1980-81 में वायपसी अधिकारियों को घटाने के बाद 1252 करोड़ रुपए की निवल विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान है। यह रकम अन्तर्रिम बजट में दिखाई गई राशि से 36 करोड़ रुपए अधिक है। इसके अतिरिक्त 1980-81 में हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भ्यास निधि से 540 करोड़ रुपए का ज्ञान मिलने की आशा है और बजट में इसके लिए इन्हीं 2करम जमा खाते में साम भी गई है।

59. भव्य बवत संघर्षों में हुई वृद्धि स्वागतीय है। इन वर्षों में अब 1980-81 में 1100 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है जबकि अन्तर्रिम बजट में 1000 करोड़ रुपए का अनुमान था। सौ करोड़ रुपए की इस वृद्धि में से 65 करोड़ रुपए राज्यों को उनके हिस्से के रूप में प्राप्त होते हैं।

60. यह निष्ठा किया गया है कि जीवन बीमा नियम, साधारण बीमा नियम और भारतीय प्रिनिट ट्रस्ट के निवेश योग्य साधनों का एक हिस्सा सरकार के विशेष नियम बाहरी में रखा जाए ताकि आयोजिता की वित्त व्यवस्था के लिए जुटाए जाने वाले साधनों में वृद्धि हो। वर्ष 1980-81 के बजट में इन जमा राशियों के लिए 100 करोड़ रुपए की प्राप्ति को हिसाब में लिया गया है।

61. अब हम सरकारी भेत्र से निवेश को बढ़ाना चाहते हैं तब हमारे लिए यह जरूरी है कि हम ऐसे निवेश को बढ़ाए रखने के लिए साधन बहुमैं की समस्या के प्रति एक नया वृद्धिकोण अपनाएं। जैसा कि सम्मानित साधारण ज्ञान में है, गैर सरकारी भेत्र की कंपनियां जमा से जमा रकमों के रूप में ज्ञान लेकर साधारण बढ़ाती हैं। सरकार यह सोचती है कि सरकारी

भेत्र की कंपनियों भी जिनके पास सक्षम व्यापारियक प्रभवकर्त्ता हैं ऐसा कर्त्ता न करें। अब हमने सरकारी भेत्र के कुछ चुने हुए पक्कों को गैर-सरकारी कंपनियों की भाँति लोगों से जमा की रकम जुटाने की इजाफत देने का केमला किया है। जब यह गोपनीयता ज्ञान पढ़नी लाभ सरकारी भेत्र के उद्देशों की बजट समर्थन पर निर्भरता कम हो जाएगी। लेकिन मैंने इस समय ऐसी किसी राशि को प्राप्ति के स्पष्ट में नहीं लिया है।

62. अन्य परिवर्तनों को नथा रेलों के याकी किराये और माल भाड़ की दरों तथा डाक और नार की शुक्र दरों के परिवर्तनों के प्रभाव को हिसाब में लेने के बाद जिनकी जर्सी में बोड्डा भागे चल कर कर्त्ता, 1980-81 में कुल मिलाकर 19827 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है, जबकि अन्तर्रिम बजट में 18980 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था। कुल मिलाकर 21467 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है। इस प्रकार करों की वर्तमान दरों के प्रतुसार 1640 करोड़ रुपए का बाटा रहेगा।

(भाग—क)

63. प्रबंध में प्रत्यक्ष करों के भेत्र से संबंधित अपने प्रस्तावों की ओर आता है। हम प्रस्तावों को तेवर करने में मैंने भीटे तोर पर कुछ बातों को व्याप में रखा है जो ये हैं: प्रत्यक्ष करों की दरे ऐसी होनी चाहिए कि लोग स्वेच्छा से ही उनका पालन करें; हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में दिए गए बजनों के प्रभुमारण में किमानों, कामगारों और मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ राहत दी जानी चाहिए, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बचनों और निवेश का स्तर ऊचा करने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। साथ ही आप और धन को टुकड़ों में बाटकर कर से बच निकलने की ओर कुछ तरकीबें व्यापक रूप से प्रबलिन हैं उनको रोकने के लिए एक समन्वित प्रयास किया जाना चाहिए।

64. हाल के बर्षों में, भीमतों में हुई वृद्धि से जो सोग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं उनमें मध्यम वर्ग भी शामिल है। सम्मानित सदस्य जानते हैं कि लूट के वर्तमान स्तर पर मग्निट भेत्र के कुशल कामगारों को भी हम समय कर देना पड़ता है। इस वर्ग के लोगों को कुछ राहत देने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि वैयक्तिक आय पर आय कर की छूट सीमा को 10000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये कर दिया जाए। इसके परिणामस्वरूप हाने वाली राजस्व की हानि को सही सीमाओं में रखने के उद्देश्य में आप के सूचन दर खण्ड को पूर्ववत् 8000 रुपये पर ही रखा जा रहा है। इसके फलस्वरूप जिन सामाजिकों में कराधेय आय 12000 रुपये से ऊपर होंगी उनमें अधिकारी को छोड़कर आय-कर का भार मौजूदा स्तरों पर ही रहेगा तथापि जहां कराधेय आय छूट सीमा से मामूली-सी ज्यादा होंगी उन मामलों में सीमान्त राहत दी जाएगी। इस प्रस्ताव से उस लाभ से ज्यादा आय-करदानाओं को लाभ पहुंचेगा।

65. सम्मानित भवत्यों को याद होगा कि प्रत्यक्ष कर जांच समिति की सिफारिश पर 1974 में वैयक्तिक आय पर आय-कर की दरें कम कर दी गई थीं और इस प्रक्रिया को 1976 में एक कदम भी आये बढ़ाया गया था जब इन दरों को और कम कर दिया गया था। दरों में इस प्रकार कमी कर दिये जाने से यह आमा बहुत हृद तक पूरी हो गई थी कि इसके कर मंबद्धी कानूनों का पहले से अधिक पालन होगा। दुर्भाग्य से इस विधा में ही रही प्रयत्नि जनता सरकार के शासन में उलट दी गई और आय-कर की किसी दरें कई अवस्थाओं में बढ़ा दी गईं। मेरे विचार से इस स्थिति को ठीक किया जाना चाहिए। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम-धूनि सभी श्रेणियों के करदानाओं के सामलों में वैयक्तिक आय पर अधिकारी की दर को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाए। इससे न केवल कर की अधिकारी सीमान्त दर 72 प्रतिशत से बढ़कर 66 प्रतिशत हो जाएगी अपितु आय के सभी वर्गों के करदानाओं को लाभ पहुंचेगा।

66. परियम्मियों की कीमतों में प्रायः तेजी से हुई कृदि को देखते हुए मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि चालू निश्चिरण वर्ष से धन कर की छूट सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाता है 1.5 लाख रुपये कर दिया जाए। किन्तु जिन मामलों में करधरेय धन इस सीमा से प्रधिक होगा उनमें करभार मौजूदा स्तरों पर ही रखा जाएगा लेकिन सीमान्त राहत पूर्ववत् दी जाती रहेगी।

67. सरकार आशा करती है कि इन रियायतों से हमारे प्रधिकांश करदाताओं को अनन्ती आय और धन के बारे में सही-पही विषया करने के लिए आक्रमणक प्रेरणा मिलेगी।

68. मैं कृत ऐसी सरकारी को भी निष्कर करना चाहता हूं जो कर के बचतों के लिए प्रधिकरत अपनाई जाती है।

69. जैपा कि सम्पादित यस्तों को भालूम है, कर संबंधी कानूनों में हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर-निधिरण एक प्रश्न तरीके से किया जाता है जिनका उचित कर-दायित्व से बच निष्करण के लिए बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि आय-कर और धन-नकर दोनों के लिए हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के आंगिक विभाजनों की मात्राएँ को बापप ले लिया जाए। पहली जनवरी 1979 को या उसके बाद किए गए आंगिक विभाजनों को कर के प्रयोजनों के लिए कार्ड मान्यता नहीं दी जाएगी और कर इस आधार पर लगा जाने रहेंगे कि मोजूदा हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब आगे भी सम्पुर्ण बना रहेगा।

70. हम समय ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों पर, जिनके एक या प्रधिक सदस्यों की स्वतंत्र आय छूट-सीमा से प्रधिक है, उन वर्गों से प्राय-कर लगता है जो व्यापियों (ईडिविज्युशन) के मामले में लगते वालों दोनों से कृत छंची है। कर-परिवर्तन (टैक्स एव्यूटेन) के प्रयोजनों के लिए हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के उपयोग को ओट सोवित करने के उद्देश्य से मैं ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के मामले में आय-कर को दरों को बढ़ाता चाहता हूं।

66 प्रतिशत की प्रधिकांश सीमान्त दर अब 50,000 रुपये से ऊपर के आय-क्षण पर लागू होगी और कुछ निचले खण्डों को दरे भी कृत छंची कर दी जाएगी। हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के कर-निधिरण के बारे में ये दो परिवर्तन कर दिए जाने से मैं आशा करता हूं कि आय की टुकड़ों में विभाजित करने और कर-दायित्व को कम करने के उद्देश्य मात्र से अनेक हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब बना लेने को प्रयत्नि कम हो जाएगी।

71. सम्पादित सदस्यों की याद द्वारा कि सरकार ते कर-परिवर्तन की तरकीब के रूप में निजी वैवेकिक न्यायों (डिस्कोमरी ट्रस्ट) के उपयोग को रोकने के लिए 1970 में कई उपाय हिए थे। किन्तु अनुसव से मानून हुआ है कि ये उपाय पूरी तरह प्रयोगशालक नहीं रहे और ऐसे न्यायों का ब्राह्मणों द्वारा समाज नहीं रोका जा सका। इस लिए मैं निजी न्यायों से संबंधित उपबन्धों को कड़ा करने का प्रस्ताव करता हूं। इस समय वैवेकिक न्यायों के सम्बन्ध में उनकी आय पर 65 प्रतिशत और उनके धन पर 1.5 प्रतिशत की समान वर आयश व्याप्ति के मामले में साधू होने वाली दर में से जो भी ऊंची दी उसी वर से कर लगता है। मेरे प्रस्ताव के अनुसार ऐसे न्यायों पर प्राय-कर प्रधिकरतम समान वर और धन-नकर 3 प्रतिशत की समान वर आयश व्याप्ति के मामले में साधू होने वाली समुचित दर में से जो भी ऊंची हो उसी वर से लगेगा। मैं निजी न्यायों के करधान के संबंध में और कई उपबन्ध करने का भी प्रस्ताव करता हूं जिनका उद्देश्य इन करों से बच निकलने के उन रास्तों को बंद कर देना है जो सरकार के व्याय में आए हैं। ये सभी उपबन्ध चालू निश्चिरण वर्ष से ही प्रभावी हो जाएंगे।

72. पूर्त और धार्मिक न्यायों का उपयोग कभी-कभी निजी स्वाधीन के लिए कारबार या उद्योग पर नियंत्रण प्राप्त करने अथवा नियंत्रण को कायम रखने के लिए किया जाता है। 1975 में हमने पूर्त और धार्मिक न्यायों की धनराशियों के निवेश का एक पद्धति निर्धारित की थी जिसे कहों में छूट प्राप्त करते रहने के लिए अपनाना जरूरी था। इन न्यायों को जैव: शर्म: और अवधारणा से इस नई निवेश-पद्धति को अपनाने की मुश्किल प्रवाप करने के उद्देश्य से भीर कामून में यह व्यवस्था की गई थी।

कि नई पद्धति को 1 अप्रैल 1978 से पहले अपनाया जा सकता है। बाद में यह नारीय 1 अप्रैल, 1981 तक बदा दी गई। इस प्रकार हिन्दू न्यायों को नई नीति के अनुसार अपने आप को बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। मैं उनको बना देना चाहता हूं कि यह समय-सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

73. हमारे कर संबंधी कानूनों का उद्देश्य हमेशा जीवन बीमा, भविष्य निधियों और अन्य ऐसे ही साधनों के जिये दीर्घकालिक बचतों को बढ़ावा देना रहा है। दुर्भाग्य से पिछले वर्ष बचतों को प्रोत्साहन देने वाले उपसम्बन्धों को प्रस्तावोत्वादकता बहुत कठिन हो गई जब बचत के लिए विषय जाने वाले प्रोपाल्हानों में एक साथ भारी कमी कर दी गई थी। सम्मानित मद्दतों को यह जानकर प्रसन्नता होती कि मैं इन बचत संबंधी प्रोत्साहनों को 1979 के बजट से पहले के स्तरों पर फिर ला देने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रकार करवाना अहंक बचतों के पहले पांच हजार रुपयों पर 100 प्रतिशत कटौती, अगले 5 हजार रुपयों पर 50 प्रतिशत कटौती और ये रागि पर 40 प्रतिशत कटौती के हक्कार होंगे।

74. गृहस्थी के क्षेत्र में बचत को बढ़ावा देने के एक और उपाय के रूप में मैं प्राय-कर दानाओं को एक विकल्प देने का प्रस्ताव करता हूं जिसके अन्तर्गत वे अपने मन्त्रिवार्य निवेश व्यायों में जरा प्रतीर्धी धनराशियों को देय नारीयों के बाद भी जरा रक्ष सकें; इसके लिए उन्हें उन जमा राशियों पर लगने वाली सौमूदा दरों पर व्याज मिला रहेगा। इसके अलावा, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि मानवनारायण भविष्य निधियों में जमा की शेष राशियों पर व्याज के संबंध में दो जाने वालों कर-छूट का उदार बना दिया जाए। इस समय ऐसे धन-राशियों पर उत्तम व्याज की रकम पर वहाँ तक प्राय-कर नहीं लगता तक कि वह रकम कर्मचारी की बेतन आप के एक तिहाई भाग से ज्यादा सही होती है। मैं इस प्रधिकरतम सीमा को हटा देने का प्रस्ताव करता हूं।

75. उद्दीप में नए पूंजी-निवेश को बढ़ावा देना आवश्यक है। साथ ही यह भी देखता होगा कि राजकोषीय प्रणाली से पूंजी-नियन्त्रण तकनीकों के पक्ष में अनुचित स्कूल न हो जाए। इन योगों उद्देश्यों को ध्यान में रखने हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि नए प्रौद्योगिक उपकरणों, जहाजों और होटलों के मंबंध में आगे भी कर-प्रवक्ताश रहे, मगर कुछ संशोधित रूप में। मेरे प्रस्ताव के अन्तर्गत नए प्रौद्योगिक उपकरणों, जहाजों या अनुमोदित होटलों के संबंध में कर-प्रवक्ताश इन योगों से हुई आय को एक विनियोग प्रतिशतता के मंबंध में ही उपलब्ध होगा। कंपनियों के मामले में इन योगों से हुए लाभों का 25 प्रतिशत भाग सात वर्ष तक कर-मुक्त रहेगा। नियमित करवानों के मामले में कर-मुक्त लाभों की प्रतिशतता 20 प्रतिशत होती। महाकाशों समिनियों के मामले में कर-प्रवक्ताश 10 वर्ष की अवधि के लिए उपबन्ध होगा, जब कि करवानों को प्राय-श्रेणियों के मामले में यह अवधारणा सात वर्ष तक रहेगा। यह विधायत उन सभी नये औद्योगिक उपकरणों के मामले में उपलब्ध होती जो 31 मार्च, 1981 के बाद लेकिन 1 अप्रैल, 1985 से पहले, यानी नई पंचवर्षीय आयोजना को अवधि के अन तक उत्पादन शुरू कर देंगे। अन्य औद्योगिक उपकरणों के लिए विधायत नयी लागू होनी यदि वे प्राय-कर प्रधिनियम की व्याख्यानी अनुसूची में सूचीबद्ध रहती हों या जोड़ी का उत्पादन नहीं करते होंगे। यह विधायत उन अनुमोदित होटलों के मामले में भी उपबन्ध होती जो उक्त अवधि में अपना काम करता थुक्क कर देंगे और उत जहाजों को भी जो उम प्रधिय में अपना काम करता थुक्क कर देने वाले होंगे।

76. खानमीर से अर्थप्रवर्त्य के कई महत्वपूर्ण श्रेणीों में निवेश को कमी की देखते हुए नए निवेश को प्रोत्साहन देना जरूरी है। नए निवेश के लिए विशेष प्रेरणा देने के लिए मैं नई प्रायोजना अवधि में लगाई गई संशोनरी या संयंत्र पर उमकी स्थापना के वर्ष में एक प्रतिरिक्षण मूल्यहास की प्रतिशतता के बाबावर होती है। प्रस्तावित अतिरिक्षण मूल्यहास जहाजों, वायुयानों, सड़क पारेवहन वाहनों, कार्यालय मूल्यहासों (एलयस) या मशीनरी अवधा संबंध पर, जो कार्यालय परिवहर अवधा निवास स्थान में लगे होंगे, उपलब्ध नहीं होगा।

77. वैज्ञानिक समूहाय में निगमन की भावता बहुत ज्यादा फैली है। यह सरकार भी भावता जानती है कि हमारे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद् भारत के आर्थिक कार्यालय में किनारा अधिक योगदान दे सकते हैं। सरकार अनुसंधान नवाय विकास संबंधी कार्यकलायों को बढ़ावा देने के लिए भी बहुतसंकल्प है। इसनिए मैं किसी आन्तरिक अनुसंधान और विकास सुविधा में किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुए वास्तविक व्यष्टि के 125 प्रतिशत के बगवार अनुपातिक कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव करता है जहा यह व्यष्टि एक ऐसे कार्यविधि पर किया गया है जो भारत की मासांत्रिक, आर्थिक और प्रौद्योगिक जलसंरक्षणों को व्यापार में रखने हुए वित्ति प्रधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, मैं अनुपातिक प्रौद्योगिकान्वयों में प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए व्यष्टि पर आनुपातिक कटौती से संबंधित मौजूदा उपर्युक्त के बोत को बढ़ावा का प्रस्ताव करता हूं ताकि सरकारी खेत की कंपनियों की आनंदिक अनुसंधान और विकास सुविधाओं में किए गए हस्ती प्रकार के व्यष्टि को भी उम उपर्युक्त में शामिल किया जा सके। मुझे कोई संदेह नहीं कि सम्मानित गवर्नर्इ इन विधायकों का स्वागत करेगा।

78. इस समय आय-कारदाराओं को वित्तीय वर्ष के दौरान अपने खुब के कथनों या अनुमानों के आधार पर प्रतिप्रयोग कर देना पड़ता है। यह सम्भावना होती है कि अनुमानित प्रतिप्रयोग कर की राशि, वर्तमान आय पर लगान बाने कर से, अनुमान के 33½ प्रतिशत से अधिक मात्रा में कम होनी वहां करदाराओं को अपने अनुमानों में बढ़ावा कर देनी पड़ती है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि कंपनियों के मामले में इस प्रति (मार्जिन) को 33½ प्रतिशत से घटा कर 20 प्रतिशत कर दिया जाए। अन्य करदाराओं के मिल कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस परिवर्तन से हम अग्रिम कर के स्वयं में देय कर का अधिक बड़ा हिस्सा कमूल कर सकते हैं और इस प्रकार इसका 1980-81 में सरकार की अर्थप्रयोग स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

79. कारबार और उत्पाद-धंधों में अधेर और विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियोजकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को किए गए वेतन के 1½ के बगवार अनुपातिक कटौती की अवधारणा की जाए। यहां यह वेतन एक वर्ष में भीत हजार रुपए से ज्यादा न हो। इसके अलावा मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अन्य और विकलांग व्यक्तियों की करारप्रयोग आय का हिस्साव लगाने में इस समय जो पांच हजार रुपए की कटौती की सुविधा उपलब्ध है उसे बढ़ा कर दम हजार रुपए कर दिया जाए।

80. इस समय, वेतन आय का हिस्साव लगाते हुए, पेंगन-भौमियों के मामले में, मानक कटौती उपलब्ध नहीं है। पेंगन-भौमियों को, जो की कीमतों की वृद्धि के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोगों में से है, कुछ गहरा देने के लिए मैं उन्हें भी मानक कटौती का नाम देना चाहता हूं।

81. अन्यराष्ट्रीय खेत-कूद प्रतियोगिकान्वयों में भाग लेने के लिए अपने खिलाड़ियों की प्रोत्साहन देने के लिए मैं उनकी विदेश में उपर्याप्त अनुरागिकी के 25 प्रतिशत आय के बगवार कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं, यदि यह अनुरागिकी भारत में विदेशी मुद्रा में लाई जाए। यह उपर्युक्त चालू नियरिंग वर्ष और उसमें बात के वर्षों के संबंध में लागू होगा। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि जीवन बीमा और अधिक नियरिंगों आय के जरिये खिलाड़ियों द्वारा की गई बचतों के संबंध में ऊची दर से कटौती की अनुमति होनी चाहिए, जैसी कि इस समय लेखकों, नाटकारों, कलाकारों, संगीतकारों और प्रतिनिधित्वादीयों के मामले में उपलब्ध है। इस प्रकार खिलाड़ियों द्वारा की गई बचतों के संबंध में ऊची दर से कटौती की अनुमति होनी चाहिए, जैसी कि इस समय लेखकों, नाटकारों, कलाकारों, संगीतकारों और प्रतिनिधित्वादीयों के मामले में उपलब्ध है। इस प्रकार खिलाड़ियों द्वारा आय के 40 प्रतिशत तक और अपनी बाकी आय के 30 प्रतिशत तक, और कुल मिलाकर अधिक से अधिक 50,000 रुपए तक की कटौती के हिस्साव होंगे।

82. 1978 में, विज्ञापन, प्रकार और विकी संघर्षन पर किए गए व्यष्टि की कटौती-भौमिका राशि के बारे में कुछ प्रतिवर्धन लगा दिए गए थे।

311 GI/80-2

इन प्रतिवर्धनों ने खाग तौर से अबू और मध्यम कारबार को नक्सान पहुंचाया है। इसनिए मैं इन प्रतिवर्धनों को हटा देने का प्रस्ताव करता हूं।

83. इस गवर्नर, मुर्गीपालन और डेरी व्यवसाय तथा पशुपालन में होने वाली आय, जिके 33½ प्रतिशत या इस हजार रुपए में से जो भी ज्यादा हो वहां तक आयकर से मुक्त है। मैं सोचता हूं कि अब समय आ गया है कि जब इन लोकों से आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी राष्ट्रीय खाजाने में कुछ ज्यादा अंशदान दें। इसनिए मैं इस प्रकार की आय के संबंध में कोई जाने वाली कटौती को ऐसी आय के एक निहाई भाग अधिकार प्रदान हजार रुपए में से जो भी कम हो उस तक मीमित करने का प्रस्ताव करता हूं।

84. इस समय, धननकर लगाने के प्रयोजनों के लिये कृषि संपत्ति को करारप्रयोग धन में शामिल किया जाता है। उम यसमय जब कि कृषि-संपत्ति को कर की परिधि में लाया गया था। यह आणा की गई भी कि यह कृषक समूहाय के ममूद वर्ग में साधान जुटाने का एक गोपक भाईदम होगी। परन्तु पिछले इस मालों में हमें जो अनुभव हुआ है वह अबूत ही निरागजनक है। कृषि सम्पत्ति पर वसूल किए जाने वाले धननकर की गणि प्रतिवर्धन प्रायः एक करोड़ रुपए से कम रही है। कृषि भूमि के मूल्यकान ने कई कठिनाइयों पैदा कर दी हैं जिनके कारण परेशान किए जाने की शिकायतें बढ़ते रही हैं। चूंकि यह कर अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति में पूरी तरह असफल रहा है, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि-संपत्ति पर धननकर लगाना बंद कर दिया जाए, किन्तु चाय, काफी, रबड़ और इनायती के वागानों के मालिकों के मामले में यह पूर्ववत् लाभ रहेगा। मुझे विश्वास है कि इस कदम का हमारे किसान भाष्यों द्वारा व्यापक रूप में स्वागत किया जाएगा।

85. मैं आयकर अधिनियम में कुछ संशोधन करना चाहता हूं जिनके उद्देश्य पैसे कुछ न्यायालयिक निर्णयों को प्रभावहीन करना है जिनके कारण कश्तालाओं को अनुकूल लाभ मिल गया है। वित्त विवेदक में प्रत्यक्ष कर्तों में संशोधन के लिए और भी कुछ प्रस्ताव हैं जिनका अधिक महत्व नहीं है। उनको स्पष्ट करने में मैं मद्दत का अद्भुत लम्ब रहूंगा।

86. प्रत्यक्ष कर्तों के संबंध में दरें घटाने और अन्य रिपायरें देने से भाग्यराजतया राजस्व में कमी होनी चाहिए। किन्तु में वर्ग विचार है कि दरें घटा देने से कर संबंधी कानूनों के पालन में बहुत ज्यादा सुधार होगा। कर-नियरिंग की लकड़ीबों की निकल करने के लिए वैज्ञानिक संशोधन कर देने से और अप्रयोग कर के उपबन्धों में परिवर्तन कर देने से अधिक राजस्व प्राप्त होना चाहिए। आयकर और धननकर संबंधी सभी प्रस्तावों के समय प्रभाव की सोटे तौर पर प्रोत्साहन करने की विधि की गणि कोई हानि नहीं होगी। किन्तु मैं यह मानता हूं कि आयकर के अन्तर्गत केंद्र और राज्यों के परस्पर हिस्सों में कुछ समाप्तिकरण करने की आवश्यकता हो सकती है। ये समायोजन वर्ष के दोगांने करन-प्रयोग की प्रवृत्तियों को बेत्ते हुए किए जाएंगे।

87. उधार देने की वर्तों में ऊपर भी और समायोजन करने से अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव कम हो जाने चाहिए। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि 30 जून, 1980 के बाद अनुसूचित वाणिज्यिक वैकों द्वारा उपर्याप्त व्याज के संबंध में व्याज-कर फिर से लागू कर दिया जाए। इस कर के आयन-प्रैद भी भी बढ़ाया जा रहा है ताकि उसमें बड़ी-बड़ी अधिक भारतीय औद्योगिक वित्त संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास वैक, भारतीय औद्योगिक अृण और विदेशी निगम, भारतीय औद्योगिक तुनवित निगम द्वारा प्राप्त व्याज की राशियों को भी शामिल किया जा सके। यह कर पहले की तरह व्याज की प्रभाव राशि पर 7 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। इस उपाय से एक पूरे वर्ष में 217 करोड़ रुपए और 1980-81 में लगभग 108.5 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

६४. लक्ष्मरी दोटों में ग्रामावास प्रौद्योगिक पर जर्जर ग्रामीण रियाजाने वाले व्यवहारों को रोकने के उद्देश्य से, मैं एक तर्फ कर लगाने के लिए चालू गत में ही एक विशेषक पेश करना चाहता हूँ। यह कर उन होटलों की सकल प्राप्तियों पर 15 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा जिसमें एक कमरे का स्वनुतम किराया 75 रुपए प्रतिदिन है। यदि नया कर 1 सितम्बर, 1980 से लागू करने का प्रस्ताव है। इस उपाय से एक पूरे वर्ष में 12 करोड़ रुपए और 1980-81 में कोई 5 करोड़ रुपए का ग्राम्य प्राप्त होगा।

६५. अब मैं अप्रत्यक्ष कर मंजूरी प्रप्ते प्रस्तावों पर आता हूँ। अपने प्रस्ताव तैयार करने हुए मैंने निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखा है। जहाँ तक अनिवार्य साधन जुटाना अनिवार्य है, वहाँ तक यह काम हम प्रकार किया जाए कि किसी भी बहुत पर बोझ बहुत जायदा न वहै। इस व्यापारों के अनुमार, हमारे लघु उद्योग जैसे को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। रोजगार और नियान्त की प्रबुरु धमता रखने वाले उद्योगों को शूल दरों में समर्पित फेर-बदल करके, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आम उपभोग की कुछ वस्तुओं पर से शूलों का अंतर कम कर दिया जाना चाहिए या विकूल ही लागू दिया जाना चाहिए।

६६. शूल में ही मैं सम्मानित सरकारों को यह बढ़ाकर निपिलन कर देना चाहता हूँ कि मेरे प्रस्ताव बहुत संतुष्टि है। आम तौर पर यह किया जाता रहा है कि कुछ चीज़ी ही ही मरों पर नए शूल लगाए जाने हैं या तुरने वस्तुओं की दरों में बढ़ि कर दी जाती है। मत्र मैंने हम तरफाई से अबने की कोशिश की है।

६७. इस वर्ष मैंने अनिवार्य कराधान के भार को विश्व-भिक्ष प्रकार की बहुत ज्यादा वस्तुओं पर हृतका हल्का फैलाने की कोशिश की है और यह भी ध्यान रखा है कि आम उपभोग की वस्तुओं पर हमका असर न पड़े। मैं इस उद्देश्य को विशेष उत्पाद-शूलक के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूँ जो अब भी उत्पाद शूल योग्य सभी वस्तुओं पर आधारित उत्पाद-शूलक के 1/20 की दर में लगता है, लेकिन बहुत सी जीजों को इससे मुक्त रखा गया है। मेरे प्रस्ताव के अनुमार, विशेष उत्पाद-शूलक उन मरों पर लगाया जाएगा जो इस समय इससे मुक्त हैं और इसकी दर लागू आधारित उत्पाद-शूलक की प्रभावी दरों के 1/20 भाग के बराबर होती है। तथापि कुछ जीजों आगे भी पूरी तरह शूल मुक्त रहती है। इस प्रकार मोटर स्प्रिंग, जिसमें लैप्पा, गिर्डों का तेल, उच्च गति डीजल तेल, हल्का डीजल तेल और इक्विपमेंट्सिलियम रैम शामिल हैं, तथा कोयले और जिजी पर विशेष उत्पाद शूल नहीं लगेगा। इसके अलावा, विद्यु-मलाई, बनस्पति और टैकिंग मद 68 के अन्तर्गत आगे वाली वस्तुओं पर भी विशेष उत्पाद-शूलक नहीं लगाया जाएगा। जहाँ प्रभावी आधारित शूलक के 1/20 की दर में पहले ही विशेष उत्पाद-शूलक लग रहा होगा उनके संबंध में भी दर को बढ़ाकर प्रभावी आधारित शूलक का 1/10 करने का प्रस्ताव करता हूँ। लेकिन यह बहुत भट्टी के तेल, एस्कल्ट, बिटुमिन और कोलाईर, अन्यथा अविनिविष्ट पैट्रोलियम उत्पाद और भस्मीभूत पैट्रोलियम कोक पर लागू नहीं होती। जीनी और संसाधित बनस्पति निर्वाचित लेंदों पर भी जीज़ी ही ही दर से शूल नहीं लगेगा। इस समय सिपारेटों पर विशेष उत्पाद-शूलक विकूल नहीं लगता, लेकिन अब उन पर आधारित उत्पाद-शूलक के 1/10 के त्रिसाथ से विशेष उत्पाद-शूलक लगेगा। इन प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में 197.71 करोड़ रुपए का ग्राम्य प्राप्त होगा। विशेष उत्पाद-शूलक संबंधी प्रस्तावों के फलस्वरूप, आयातित वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शूलों के रूप में, 16.75 करोड़ रुपए की और प्राप्ति होगी।

६८. लोडा एंग और कास्टिक सोडे की लगातार कमी रहने के कारण बाजार में इन वर बहुत ज्यादा ग्रीमियम मिलता है। मैं इन उत्पादों पर लगाने वाले उत्पाद-शूलक को 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत मूल्यानुमार बढ़ाकर इन ग्रीमियम के कुछ हिस्सों को बढ़ाव लेना चाहता हूँ। मैं यह भी ग्राम्य करना हूँ कि मोड (स्टार्च) पर लगाने वाले उत्पाद-शूलक की दर को 10 अनिवार्य बढ़ाकर 15 प्रतिशत मूल्यानुमार कर दिया जाए।

६९. नेगा कुर्डों ये ग्राम्यानुकूल उत्पाद जो इसे ग्राम्यानुकूलता के साथ समान स्तर पर आ जाएं जिन पर ग्राम्य स्तर में इस शूल 15 प्रतिशत मूल्यानुमार भी दर से उत्पाद-शूलक लगता है। मैंनिविष्ट रबड़ पर इस समय 5 प्रतिशत मूल्यानुमार की बहुत जीवी दर से शूलक लगता है। राजस्व के उपाय के स्तर में मैं मैंनिविष्ट रबड़ पर लगाने वाले उत्पाद-शूलक को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत मूल्यानुमार करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इसी प्रकार विनिविष्ट तेजाओं पर लगाने वाले उत्पाद-शूलक की दरों को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत मूल्यानुमार किया जा रहा है। इन उपायों से एक पूरे वर्ष में 18.93 करोड़ रुपए का अनिवार्य ग्राम्य प्राप्त होगा।

७०. ग्राम्य प्राप्त करने की दृष्टि से ही मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि भीने पर इस समय केन्द्रीय उत्पाद-शूलक टैकिंग की मद 68 के अन्तर्गत जो 8 प्रतिशत के हिसाब से शूलक लगता है उसकी वजाय केन्द्रीय उत्पाद शूलक टैकिंग में ही एक अलग मद के अन्तर्गत 30 रुपए प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से मात्रानुमार शूलक लगाया जाए। लेकिन यह शूलक वैश्वीम पैन वाली जीनी मिलों में उत्पादित भीने पर ही लगाया जाने का प्रस्ताव है। खाण्डसारी के फलस्वरूप मैं उत्पादित शीरा जो लगाने के काम भी आवश्यक है, शूलक-मुक्त रखता जाएगा। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप एक वर्ष में 4.24 करोड़ रुपए की ग्राम्य प्राप्ति होने का अनुमान है।

७१. अब मैं उन प्रस्तावों की ओर आता हूँ जो देशी उद्योग के कनिष्ठ प्रौद्योगिकों को पहले से अधिक मात्रा में संरक्षण देने के लिए तैयार किए गए हैं। वहाँ प्रस्ताव आडिमोफीसेन्टी ट्रैस्मीकापरों के संबंध में है; यह मद लघु जैव के लिए मूल्यानुमार रखती रही है। इस मद के आयातों के प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए मैं आयातों पर लगाने वाली सीमा शूलक को 75 प्रतिशत में बढ़ाकर 120 प्रतिशत मूल्यानुमार करना चाहता हूँ। भेरा दूसरा प्रस्ताव आयातित कोरी जीनी पाजिटिव गिर्डों के बारे में है जिनके संबंध में आधारित सीमा शूलक को 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया प्रति लीनियर मीटर कर देने का प्रस्ताव है ताकि इसमें भरकारी धैर्य का एसी फिल्में बनाने का कारबाना आयातित फिल्मों के मूकाबले में ठहर सके। देशी कम्प्यूटर उद्योग को संरक्षण देने के उद्देश्य से मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि आयातित कम्प्यूटरों पर लगाने वाले प्रति-प्रतिसूलनकारी शूलक को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत मूल्यानुमार कर दिया जाए। इन उपायों से एक पूरे वर्ष में लगाया 1.83 करोड़ रुपए का अनिवार्य ग्राम्य प्राप्त होने की उम्मीद है।

७२. अप्रत्यक्ष करने के क्षेत्र में मैं ग्राम्य सम्बन्धी केवल एक प्रस्ताव और है। इसका सम्बन्ध याक्रियों के सामान से है। जैसा कि सम्मानित समस्या जानते हैं, 1978 में याक्रियों के सामान पर भी जीने वाली शूलों को काफी उदार बना दिया गया था और थोड़े समय के लिए विदेशी यात्रा पर जीने वाली भारतीय याक्रियों के लिए समान रूप से ये छोटे उदार बना दी गई थीं जिनके परिणामस्वरूप उन्हें 1,000 रुपए तक के मूल्य के सामान को बिना शूलक दिया और 2000 रुपए तक के मूल्य की वस्तुओं को शूलक प्रदा करने की अनुमति थी। इस उदारीकरण के बावजूद, कई याक्रियों द्वारा याक्री-सामान की किसी भी वस्तुओं का अनुमत सीमाओं से कही अधिक मात्रा में बराबर आयात किया जाता रहा। इसका मुख्य कारण यह है कि लोग विदेशी जीजों के पीछे पायान से हों रहे हैं और इन वस्तुओं को भारत में बेचने पर काफी मुश्का होता है। अनुमत सीमाओं से अधिक याक्री-सामान का आयात किए जाने की स्थिति में याक्रियानियन्यत की कार्रवाई भारतीय करता जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे ग्राम्य-राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर याक्रियों की गति धीमी हो जाती है। मैंने इस समस्या पर विचार किया है और इस संबंध में मैं दो प्रस्ताव नहीं रखता। पहला जो वाले उत्पाद-शूलकों की भारी सामान की विदेशी जीजों के पीछे पायान से हों रहे हैं और इन वस्तुओं को भारत में बेचने पर काफी मुश्का होता है। अनुमत सीमाओं से अधिक याक्री-सामान का आयात किए जाने की स्थिति में याक्रियानियन्यत की कार्रवाई भारतीय करता जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे ग्राम्य-राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर याक्रियों की गति धीमी हो जाती है। मैंने इस समस्या पर विचार किया है और इस संबंध में मैं दो प्रस्ताव नहीं रखता। पहला जो वाले उत्पाद-शूलकों की भारी सामान की विदेशी जीजों के पीछे पायान से हों रहे हैं और इन वस्तुओं को भारत में बेचने पर काफी मुश्का होता है। अनुमत सीमाओं से अधिक याक्री-सामान का आयात किए जाने की स्थिति में याक्रियानियन्यत की कार्रवाई भारतीय करता जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे ग्राम्य-राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर याक्रियों की गति धीमी हो जाती है। मैंने इस समस्या पर विचार किया है और इस संबंध में मैं दो प्रस्ताव नहीं रखता। पहला जो वाले उत्पाद-शूलकों की भारी सामान की विदेशी जीजों के पीछे पायान से हों रहे हैं और इन वस्तुओं को भारत में बेचने पर काफी मुश्का होता है। अनुमत सीमाओं से अधिक याक्री-सामान का आयात किए जाने की स्थिति में याक्रियानियन्यत की कार्रवाई भारतीय करता जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे ग्राम्य-राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर याक्रियों की गति धीमी हो जाती है। मैंने इस समस्या पर विचार किया है और इस संबंध में मैं दो प्रस्ताव नहीं रखता। पहला जो वाले उत्पाद-शूलकों की भारी सामान की विदेशी जीजों के पीछे पायान से हों रहे हैं और इन वस्तुओं को भारत में बेचने पर काफी मुश्का होता है। अनुमत सीमाओं से अधिक याक्री-सामान का आयात किए जाने की स्थिति में याक्रियानियन्यत की कार्रवाई भारतीय करता जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे ग्राम्य-राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर याक्रियों की गति धीमी हो जाती है। मैंने इस समस्या पर विचार किया है और इस संबंध में मैं दो प्रस्ताव नहीं रखता। पहला जो वाले उत्पाद-शूलकों की भारी सामान की विदेशी जीजों के पीछे पायान से हों रहे हैं और इन वस्तुओं को भारत में बेचने पर काफी मुश्का होता है। अनुमत सीमाओं से अधिक याक्री-सामान का आयात किए जाने की स्थिति में याक्रियानियन्यत की कार्रवाई भारतीय करता जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे ग्राम्य-राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर याक्रियों की गति धीमी हो जाती है। मैंने इस समस्या पर विचार किया है और इस संबंध में मैं दो प्रस्ताव नहीं रखता। पहला जो वाले उत्पाद-शूलकों की भारी सामान की विदेशी जीजों के पीछे पायान से हों रहे हैं और इन वस्तुओं को भारत में बेचने पर काफी मुश्का होता है। अनुमत सीमाओं से अधिक याक्री-सामान का आयात किए जाने की स्थिति में याक्रियानियन्यत की कार्रवाई भारतीय करता जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे ग्राम्य-राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर याक्रियों की गति धीमी हो जाती है। मैंने इस समस्या पर विचार किया है और इस संबंध में मैं दो प्रस्ताव नहीं रखता। पहला जो वाले उत्पाद-शूलकों की भारी सामान की विदेशी जीजों के पीछे पायान से हों रहे हैं और इन वस्तुओं को भारत में बेचने पर काफी मुश्का होता है। अनुमत सीमाओं से अधिक याक्री-सामान का आयात किए जाने की स्थिति में याक्रियानियन्यत की कार्रवाई भारतीय करता जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे ग्राम्य-राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर याक्रियों की गति धीमी हो जाती है। मैंने इस समस्या पर विचार किया है और इस संबंध में मैं दो प्रस्ताव नहीं रखता। पहला जो वाले उत्पाद-शूलकों की भारी सामान की विदेशी जीजों के पीछे पायान से हों रहे हैं और इन वस्तुओं को भारत में बेचने पर काफी मुश्का होता है। अनुमत सीमाओं से अधिक याक्री-सामान का आयात किए जाने की स्थिति में याक्रियानियन्यत की कार्रवाई भारतीय करता जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे ग्राम्य-राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर याक्रियों की गति धीमी हो जाती है। मैंने इस समस्या पर विचार किया है और इस संबंध में मैं दो प्रस्ताव नहीं रखता। पहला जो वाले उत्पाद-शूलकों की भारी सामान की विदेशी जीजों के पीछे पायान से हों रहे हैं और इन वस्तुओं को भारत में बेचने पर काफी मुश्का होता है। अनुमत सीमाओं से अधिक याक्री-सामान का आयात किए जाने की स्थिति में याक्रियानियन्यत की कार्रवाई भारतीय करता जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे ग्राम्य-राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर याक्रियों की गति धीमी हो जाती है। मैंने इस समस्या पर विचार किया है और इस संबंध में मैं दो प्रस्ताव नहीं रखता। पहला जो वाले उत्पाद-शूलकों की भारी सामान की विदेशी जीजों के पीछे पायान से हों रहे हैं और इन वस्तुओं को भारत में बेचने पर काफी मुश्का होता है। अनुमत सीमाओं से अधिक याक्री-सामान का आयात किए जाने की स्थिति में याक्रियानियन्यत की कार्रवाई भारतीय करता जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे ग्राम्य-राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर याक्रियों की गति धीमी हो जाती है। मैंने इस समस्या पर विचार किया है और इस संबंध में मैं दो प्रस्ताव नहीं रखता। पहला जो वाले उत्पाद-शूलकों की भारी सामान की विदेशी जीजों के पीछे पायान से हों रहे हैं और इन वस्तुओं को भारत में बेचने पर काफी मुश्का होता है। अनुमत सीमाओं से अधिक याक्री-सामान का आयात किए जाने की स्थिति में याक्रियानियन्यत की कार्रवाई भारतीय करता जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे ग्राम्य-राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर याक्रियों की गति धीमी हो जाती है। मैंने इस समस्या पर विचार किया है और इस संबंध में मैं दो प्रस्ताव नहीं रखता। पहला जो वाले उत्पाद-शूलकों की भारी सामान की विदेशी जीजों के पीछे पायान से हों रहे हैं और इन वस्तुओं को भारत में बेचने पर काफी मुश्का होता है। अनुमत सीमाओं से अधिक याक्री-सामान का आयात किए जाने की स्थिति में याक्रियानियन्यत की कार्रवाई भारतीय करता जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे ग्राम्य-राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर याक्रियों की गति धीमी हो जाती है। मैंने इस समस्या पर विचार किया है और इस संबंध में मैं दो प्रस्ताव नहीं रखता। पहला जो वाले उत्पाद-शूलकों की भारी सामान की विदेशी जीजों के पीछे पायान से हों रहे हैं और इन वस्तुओं को भारत में बेचने पर क

हृष्ट पूर्व वर्ष में 20 करोड़ रुपए की प्रतिशत प्राप्ति होगी। हृष्ट उपाय में, जो शीघ्र ही लागू किया जाएगा, अनुमत सीमाओं से अधिक आयात किए गए यात्री-सामान पर 320 प्रतिशत की समान दर पर शुल्क लगाया जाएगा, अर्थात् यह शुल्क, निष्ठानक प्रथवा 150 प्रतिशत का शुल्क देकर लाए जा सकते वाले यात्री-सामान से अधिक सामान के आयात पर लगाया जाएगा। फिलहाल ऐसी वस्तुओं का लापा जाना बिना लाइसेंस का आयात मात्रा जाता है और इसका उत्तेजना किया जा सकता है, प्रथवा उन पर शुरूआती या वृद्धि लगाया जा सकता है ताकि इन वस्तुओं को बेचने पर जो मुनाफा होता ही उत्तेजना कर दिया जाए। शुल्क की दर बढ़ाने का उद्देश्य यह है कि व्यायानिणयन की लंबा रामय सेने वाली प्रत्रिया से गुजराता न पड़े और इन जरूरियों और दण्डों के स्थान पर इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। लेकिन ऐसी वस्तुओं के मंदिर में जो स्पष्टता, व्यापारिक किस्म की होगी अब भी दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती।

98. मैंने कुछ और भी प्रस्ताव हैं जो अनिवार्यतः करने को यज्ञिन-समग्र बनाने के उपायों के रूप में हैं। पहला बातिन जल (प्रयाणित वाटर) के संबंध में है। प्रस्ताव है कि सर्वानुकरण के उद्देश्य से, उत्पाद-शुल्क के प्रयोगन में कैफीत बाले और बिना कैफीत के बातिन जल के वर्तमान भेद को समाप्त कर दिया जाए और इसके लिए भी प्रकार के सुविधित बातिन जल पर 40 प्रतिशत मूल्यानुमान की समान दर में शुल्क लगा दिया जाए। इस प्रस्ताव का गत्यव प्रभाव नगण्य होगा।

97. मैंने 1979 के बजट में, दियासतार्ह उद्योग पर लागू उत्पाद-शुल्कों के दाँच में किए गए परिवर्तनों ने उत्पन्न ममस्याओं पर काफी विचार किया है। यसका कुटीर उद्योग थेट्र को दिए गए लाभों को बराबर बनाए रखने की व्यष्टि आवश्यकता है, लेकिन इस का प्रयोग यह नहीं कि अर्थवीकृत मध्यवर्ती क्षेत्र को कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में घुमगैठ करने दी जाए। इस बात की मुनिष्वित व्यवस्था करने के लिए कि शुल्क की नीची दर का साम केवल कुटीर उद्योग थेट्र के अमली एकों को ही प्राप्त हो, भेग यह प्रस्ताव है कि दियासतार्हों पर शुल्क की रियायत को अनु-मोदित लेवलों वाली और व्यावधारी ग्रामोंशांग आयोग, गर्जों के अधिकरणों तथा पंचीकृत महकारी समितियों को देखी गई हो या उनके माध्यम से वर्षी जाने वाली दियासतार्हों तक सीमित कर दिया जाए। इसके गाथ-माथ, मुझे कुटीर क्षेत्र के संबंध में शुल्क की रियायती दर पर दियासतार्हों की निकासियों की मौजूदा सीमाओं का कोई औरियत प्रतीत नहीं होता। अतः मैं कुटीर क्षेत्र के एकों बारा किए गए उत्पादन पर लगी मौजूदा सीमाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव करना हूँ। मुझे विद्वान है कि इन मिले जुले उपायों के कुटीर क्षेत्र के दियासतार्ह उद्योग का नेतृत्व में विकास होगा।

98. बीड़ी उद्योग के उन निर्माताओं द्वारा किये जाने वाले कवाचार की शिकायतें भिली हैं जो बिना आण्ड की बीड़ी के क्षेत्र पर लागू छूट की उदार सीमा का, जो इस समय 60 लाख बीड़ी प्रति निर्माता प्रतिवर्ष है, नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इस कवाचार की संभावनाओं का कम करने के उद्देश्य से मैं यह प्रस्ताव है कि छूट की सीमा को कम करके बिना आण्ड की 30 लाख बीड़ी प्रति निर्माता प्रतिवर्ष कर दिया जाए। इससे अब भी वे निर्माता उत्पाद-शुल्क के जाल से बाहर रह जाएंगे जो वास्तव में छोटे हैं और अपना धधा खुद करते हैं। इसका उद्देश्य कार्रवाई राजस्व उत्पादन नहीं है।

99. वित्त विधेयक के कुछ उपवर्धनों का उद्देश्य कनिपय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टेरिफ की मद्दत की युक्तिमंगल बनाना या उनकी स्पष्ट परिमापा करना है, ताकि उन मद्देहों या कठिनाइयों का दूर किया जा सके जो हमारे ध्यान में आई है। इन उपायों का व्यौग बजट-पत्रों में लेखा जा सकता है।

100. ग्रामी व्यापारकर्मी में दो जाने वाली रियायतों की पार आता है। हमारी अर्थव्यवस्था में छोटे निर्माता की भूमिका काफी महत्वपूर्ण

है। मैं चाहता हूँ कि बड़े निर्माता की नुकता में उसकी प्रतियोगितात्मक स्थिति में और सुधार ही और इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था का उत्पाद-विधेयक आधार और व्यापक हो। यहीं एक भाव ऐसा उपाय है जिससे हम आधिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोक सकते हैं। उत्पाद-शुल्क योग्य 70 वस्तुओं के निर्माताओं पर लागू होने वाली शुल्क संबंधी रियायतों की एक योजना पहले में ही भीजूँ है जिसके अन्तर्गत एक वर्ष में 5 लाख रुपए तक के मूल्य की निकासियों को शुल्क से छूट दी गई है। मैं अब इस रियायत का दो पहलुओं में उदार बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। पहला पहली तो यह है कि मैं इस योजना के अन्तर्गत वस्तुओं के दो और समझौतों को शामिल करना चाहता हूँ। ये हैं: राज्यान अर्थवीकृतियम बैंकोंमेट, लैनिंग पाइडर, केलिंगम कार्डिड नया कृतिम व मिथेटिक रेलिन और प्लास्टिक सामग्री। इनके अलावा कागज और कागज के गते से समझौते क्षेत्र को और व्यापक बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर अधिक महत्व पूर्ण रियायत, जिसे मैं वेता चाहता हूँ यह है कि इस योजना के अन्तर्गत आने वाली सभी वस्तुओं के बारे में 5 लाख रुपए और 15 लाख रुपए के बीच की निकासियों पर इस समय जो सामान्य उत्पाद-शुल्क की दर लगती है उसके मुकाबले केवल उसकी तीन-चौथाई दर लागू होगी। इस उपाय से बड़ी संख्या में छोटे निर्माताओं को लाभ पहुँचेगा। इसके परिणामस्वरूप पूरे वर्ष में राजस्व की लगभग 6-50 करोड़ रुपए की हानि होगी।

101. फ़िक्रे वर्ष के बजट में एक ऐसा परिवर्तन किया गया था जिसका केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टेरिफ की अवधिष्ठ दर 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के बहुमूल्यक लष्ट निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा था। सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि निःशुल्क निकासियों की मात्रा 30 लाख रुपए से घटाकर 15 लाख रुपए कर दी गई थी। मैंने इस परिवर्तन का तब भी विरोध किया था। ऐसे छोटे निर्माताओं को पैश आने वाली कठिनाईयों को दूर रखने के उपाय के रूप में मैं 30 लाख रुपए वार्षिक तक की निकासियों को उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। पूरे शब्दों में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टेरिफ की दर 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के छोटे निर्माता जिनके मंदिर और समीनों पर 10 लाख रुपए से अधिक पूरी तरह लगती हो, एक वित्तीय वर्ष में 30 लाख रुपए तक के माल की पहली निकासी पर शुल्क से पूरी छूट देने के पाव दूँगे, यद्यते कि उससे पिछले वर्ष उनकी निकासियों का मूल्य 30 लाख रुपए से अधिक न हो। चालू वित्तीय वर्ष के शेष भाग के लिए पूरी छूट को पाव निकासियों की मात्रा नदनुला कम करके निर्वात की जाएगी। इस रियायत से पूरे वर्ष में 2-4 करोड़ रुपए की हानि होने की संभावना है।

102. वेश में कागज और संबद्ध उत्पादों की कमी है और इस क्षेत्र में तकाल कोई नहीं पूँजी नहीं लगाई जा रही है। उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादित कागज और कागज के गते पर लागू मौजूदा 30 प्रतिशत मूल्यानुमान की दर के स्थान पर 20 प्रतिशत मूल्यानुमान की रियायतों दर लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ जिन कारबानों की पिछले वित्तीय वर्ष की निकासियों की मात्रा 300 मीट्रिक टन कागज और कागज के गते से अधिक न हो। इस रियायत से पूरे वर्ष में एक करोड़ रुपए से कुछ कम की हानि होती है।

103. इलेक्ट्रोनिकी उद्योग में रोजगार और निर्यात की काफी समाप्तनाएँ हैं। हमारे पास आवश्यक कौशल और विशेषज्ञता मौजूद है और उचित राजस्वकारी और सामाजिकों के जरिए इलेक्ट्रोनिकी उद्योग का विकास करने के प्रयोगन से इनका बड़े पैमाने पर लाभ उठाया जाना चाहिए। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लघु निर्माता के लिए आगे बढ़ने की बड़ी गूंजाश है। अतः इस उद्योग के लिए मैं शुल्कों में कुछ रियायतों का प्रस्ताव करता हूँ। पूरी तरह मूल्यानुमान और उपकरणों जैसी विनियिष्ट मर्दाने पर, जिनकी इलेक्ट्रोनिकों उद्योग को आवश्यकता होती है और जिनका देश में उत्पादन नहीं होता, मीमांशुल्क में कटौती कर दी जाएगी। ऐसी मर्दाने पर मीमांशुल्क की वर्तमान दर (जो कुछ मामलों में 80 प्रतिशत मूल्यानुमान तक जाती है)

घटाकर कुल 25 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दी जाएगी। इसी प्रकार, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिए आवश्यक विनियोग कल्यान समय और संघटकों पर लगने वाले सीमा-ग्रुप्प की दरों के वर्तमान स्तर को (जो कुछ मामलों में 200 प्रतिशत मूल्यानुसार से भी ऊँचा है) घटाकर 45 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए और प्रतिसंतुलन-कारी-शुल्क भी लगता रहे जहाँ मद 68 के अन्तर्गत उत्पाद-शुल्क लगता है। इन रियायतों से राजकोष को पूरे वर्ष में 4.7 करोड़ रुपए की हानि होगी।

104. अन्य देशों के अनुभव में पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिकी की उपभोक्ता वस्तुओं के विकास से कुछ समय बाकी इलेक्ट्रॉनिकी की अन्य अन्याधिक वस्तुओं के उत्पादन में बड़ी सुविधा हो जाती है। टेलीविजन सेवाएँ और शिक्षा का एक सशक्त माध्यम है। इस विकास से कि अधिक से अधिक लोगों को हम माध्यम से लाना हो, मैं सस्ते टी.वी. सेटों पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क को 15 प्रतिशत मूल्यानुसार से घटाकर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार और इसी प्रकार अन्य टी.वी. सेटों पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क को 30 प्रतिशत मूल्यानुसार से घटाकर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ। इन रियायतों में एक वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

105. इसी प्रकार रेडियो भी शिक्षा और मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसका उपयोग अधिक व्यापक रूप से किया जाता है। सरकार का विकास है कि एक और दो बैंड वाले रेडियो मेटों को बास तोर पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। ऐसे सेटों पर लगने वाली लाइसेंस फीस बहुत घुमसी रही है और इसमें ग्रामीण जनता द्वारा रेडियो सेट खरीदने के मार्ग में रुकावट भाती है। अतः मैं एक और दो बैंड वाले रेडियो सेटों तक ट्रांसिस्टर सेटों पर से यह लाइसेंस फीस विकृत हुठा देने का प्रस्ताव करता हूँ। मूल्य विवाद है कि इसका महत्व स्वागत होगा। इस छूट से सरकार को लगभग 4 करोड़ रुपए की हानि होगी।

106. हमारा कम्प्यूटर उद्योग अन्य देशों की तुलना में अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही है। देश में कम्प्यूटरों के उत्पादन को अतिरिक्त प्रोत्तराहन देने के विकास से मैं देश में बने कम्प्यूटरों पर लगे उत्पाद-शुल्क को 25 प्रतिशत मूल्यानुसार से घटाकर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ।

107. जहाज-निर्माण एक उच्च प्रारम्भिकता वाला उद्योग है और अब देश को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस समय भारतीय जहाज-निर्माण उद्योग को विवेशी जहाज निर्माणियों से प्रतियोगिता करने में अधिकाधिक कठिनाई का सामना करता पड़ रहा है। अतः मैं जहाज बनाने वाले भारतीय कारखानों में बने समुद्रगामी जहाजों के लिए उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। चापू वर्ष में इस राहत के कारण लगभग 5 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी।

108. सम्मानित सदस्य जानते हैं कि उद्योगों की पूँजीगत स्वागत का कम करने के उपाय के रूप में सरकार देशी बुटिकोण रहित कुछ युनी द्वाई मशीनों के संबंध में आयात-शुल्क को 25 प्रतिशत मूल्यानुसार तक घटाने की पद्धति का अनुसरण करती रही है। इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए मैं इस अपेक्षा पूँजीगत मशीनों की बारह और मर्दों पर लगे आयात-शुल्क को 25 प्रतिशत मूल्यानुसार तक घटाने का प्रस्ताव करता हूँ। मशीनों की इन मर्दों में भूमा उद्योग में काम आने वाली हाई स्पीड लैटर प्रेस, रोटरी और आक्सेट रोटरी प्रिंटिंग मशीनें, मोनो/लाइनों टाइप कास्टिंग मशीनों आदि जैसी पांच मर्दों शामिल हैं। इन रियायतों से पूरे वर्ष में 1.84 करोड़ रुपए के राजस्व से हाथ धोना पड़ेगा।

109. हाई प्रेशर गैस सिलिंण्डर की लागत गैस उद्योग की कुल पूँजी-गत स्वागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। इस पूँजी परिवर्त्य का कुछ हद तक कम करने की दृष्टि से मैं हाई प्रेशर गैस सिलिंण्डरों के निर्माण के लिए आयात की जाने वाली इसात की दृश्यों को सीमा-शुल्क से

पूरी तरह सुक करने का प्रस्ताव करता हूँ। साथ ही मैं ऐसे सिलिंण्डरों पर लगने वाले वर्तमान 15 प्रतिशत मूल्यानुसार उत्पाद-शुल्क को घटाकर 8 प्रतिशत मूल्यानुसार तक करने का भी प्रस्ताव करता हूँ जिन पर मद 68 के अन्तर्गत उत्पाद-शुल्क लगता है। इन दोनों उपायों से कुल मिलाकर पूरे वर्ष में 1.89 करोड़ रुपए की हानि का अनुमान है।

110. मेरा एक सामान्य रूप से लागू होने वाला प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य उन उत्पाद-शुल्क-योग्य वस्तुओं के निर्माणियों का मुक्तिधा प्रदान करना है जिनके निर्माण में ऐसी अवृत्ति काम में लाई जाती है जिन पर उत्पाद-शुल्क लगता है। ऐसे मामलों में राहत पहुँचाने के लिए इस समय दो वर्षों के अपनाएँ जाते हैं। इनमें एक है जिसे मूँजे का नरीका (मेट ब्राफ प्रोमीजर) कहा जाता है। यहाँ से है केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमों के नियम 56 के अन्तर्गत प्रीकार्मा केंटिंग का नरीका। प्रीकार्मा केंटिंग के नरीके को प्रायः निर्माणियों के लिए अधिक लाभप्रद और कम कट्टकर माना जाता है। अतः मैं मूँजे के नरीके के आधार पर दी जाने वाली वर्तमान रियायतों के स्वातंत्र्य पर प्रीकार्मा केंटिंग के नरीके के आधार पर एसी ही रियायत देने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे विवरण है कि इस उपाय का उद्योग हारा स्वागत किया जाएगा।

111. मुझे सम्मानित सदस्यों को यह याद लिनाने हुए थोड़ा कष्ट हो रहा है कि पिछले वर्ष के बजट में आम उपभोग की कई वस्तुओं पर काफी हद तक उत्पाद-शुल्क बढ़ा दिया गया था। मैं इस प्रदूषितों को उल्ट देने का प्रस्ताव करता हूँ। अतः

- तीम प्राण-रक्षक दवाओं को उत्पाद-शुल्क से बिल्कुल छूट दें दी गयी है। इन दवाओं की सूची की समय-समय पर ममीका की जाती रहेगी ताकि जहरन पहुँचे पर इसमें और दवाएँ भी जोड़ी जा सकें।
- कंट्रोल का कपड़ा समाज के कमज़ोर वर्षों के लिए होता है और उसकी कीमत कम से कम होती चाहिए। इस लिए मैं कंट्रोल के कपड़े को उत्पाद-शुल्क से बिल्कुल मुक्त कर देने का प्रस्ताव करता हूँ।
- सूती और सूती-विस्केस होजिरी, जिसमें नियमित जैसी मद्देयां हैं, अपेक्षाकृत कम मूल्य की होती है और होजिरी की इन मर्दों पर 8 प्रतिशत की दर से उत्पाद-शुल्क लगता है। मैं इन्हें उत्पाद-शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर देने का प्रस्ताव करता हूँ।
- माईक्रोल गरीब प्रादीपी की सदाचारी है। इसलिए मैं माईक्रोलों और मद 68 के अन्तर्गत प्राने वाले साईकिलों के मुर्जों को उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।
- मिनाई की मणीत के बिना गृहिणी का काम बिल्कुल नहीं चल सकता और समाज के कमज़ोर वर्ष इन मणीतों से रोज़ी भी कमाते हैं। इन पर उत्पाद-शुल्क से बिल्कुल छूट दें दी जाएगी।
- प्रैशरकूकर से गृहिणी के रोज़मरी के काम में महेनत की काफी बचत होती है और साथ ही इसमें ईंधन भी अवृत्त है। प्रैशरकूकरों पर इस समय 15 प्रतिशत की दर से जो उत्पाद-शुल्क लगता है मैं इसे कम कर के 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

112. मैं रोज़मरी के काम आने वाली कई और वस्तुओं पर लगे उत्पाद-शुल्क में काफी कटौती करने का प्रस्ताव करता हूँ। अतः

- नहाने के सादून की मस्ती विस्मों पर उत्पाद-शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाएगा;
- दृश्य पेस्ट पर लगने वाला उत्पाद-शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा;

— बैक्सूम और रीम वाले 60 बाट तक के बल्दों पर उत्पाद-शुल्क 15 प्रतिशत में धंटा कर 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

113. मुझे विश्वास है कि इन काफी विधायकों का जितने राजकोप को पूरे वर्ष में लगभग 15 करोड़ रुपए की बढ़ति होगी, समझ और जनता द्वारा स्वारंपत्र किया जाएगा। मैं यह भी आशा करता हूं कि उद्योग और व्यापारी वर्ष उपभोक्ता के माध्य उचित अध्यवाहक करने और उत्पाद-शुल्क में की गई इन कटौतियों का फायदा प्राप्त उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं।

114. हमारी पार्टी के चुनाव धोषणापत्र में टैक्सियों को छीजल में चलने के सम्बन्ध में प्रोत्तमाहन देने की बात कही गई है। हम वायदे को पूरा करने और टैक्सी मालिकों को अपनी टैक्सियों में हीजल हंजन लगाने के लिए प्रोत्तमाहन देने के प्रयोजन से मैं वेटो ते चलने वाली टैक्सियों के हंजनों को छीजल में बदलने की सूचत में छीजल हंजनों को उत्पाद-शुल्क में पूरी छूट देने का प्रस्ताव करना है।

115. मेरे धूमरे प्रस्ताव का उद्देश्य साईकिल रिक्षाचालकों को राहत देना है। मोटर से चलने वाले रिक्षे पहुंचे से ही उत्पाद-शुल्क से मुक्त हैं। मोटर के बिना चलने वाले रिक्षों को मोटर से चलने वाले रिक्षों में बदलने के लिए प्रोत्तमाहन करने के उद्देश्य से मैं इस काम में आगे बढ़े अत्तर्वाहन हंजनों को उत्पाद-शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे विश्वास है कि अस्मानित सदस्य मेरे हस प्रस्ताव का स्वारंपत्र करेंगी क्योंकि इसमें नितव्य ही यह म्पष्ट ही जाएगा कि हम शारीरिक श्रम को कम करने और सवारी के इस स्तरे माध्यम से बढ़ावा देने के लिए कितने उत्सुक हैं।

116. अप्रत्यक्ष करों की बात मामाल करने से पूर्व मुझे नीति सम्बन्धी एक प्रमुख धोषणा करती है। पिछले बीस वर्षों से लोग अप्रत्यक्ष करों की भाँति सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के मामलों के निपटारे के लिए एक स्वतंत्र प्रधीनीय स्थायाधिकरण की स्थापना की भाँति करते रहे हैं। हाल में संसद की प्रावक्तन मन्त्रिति ने भी इस मांग का समर्थन कर दिया है। गत वर्षों में सरकार हस प्रकार की किसी व्यवस्था के पक्ष में नहीं थी क्योंकि ऐसा महसूस किया जाता था कि अप्रत्यक्ष करों के मामलों में ऐसा करना उचित नहीं होगा और यह भी कि बर्तमान विभागीय संघ का वृष्टिकोण बहुत है अत्युपरक रहता है। मेरे विचार में अब ऐसा समय आ गया है जब हमें हम प्राप्त गाय की मार्गीनता के भाव स्वीकार कर नेता चाहिए जो हम तीनिंवाद्य पर आधारित है कि न्याय न केवल किया ही जाए बल्कि किया हुआ रिकार्ड भी हो। इसी भाव में प्रेसिन होकर विन विवेषक में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और स्वर्ण नियवण के मामले में अपीलों की सुनवाई के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना करने की अवस्था की गई है। यह न्यायाधिकरण उस कार्यपालक संघ से विस्तृत स्वतंत्र होगा जिस पर राजस्व विवेषक कानूनों के राजमर्ग के प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। मुझे हम में कोई मन्दहृत नहीं कि संसद और व्यापार नथा उद्योग हम उपाय का तहे दिन से अनुमोदन करेंगे।

117. मेरे कर प्रस्तावों में पूरे वर्ष में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों में 223.22 करोड़ रुपए की और सीमा शुल्कों में 39.58 करोड़ रुपए की प्राप्ति होती। मैंने जित राहतों की धोषणा की है उनमें से 34.75 करोड़ रुपए की राहत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों के अन्तर्गत और 7.93 करोड़ रुपए की राहतों सीमा-शुल्क के अन्तर्गत आती है। हम प्रकार कुल प्रसारक, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों में 188.47 करोड़ रुपए, और सीमा शुल्कों में 31.65 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति होती। पूरे वर्ष में इनसे केन्द्रीय राजकोप में 144.85 करोड़ रुपए की छूट होती और राज्यों का हिस्सा 75.27 करोड़ रुपए होगा।

118. जिन मामलों में परिवर्तनों की अधिसूचनाओं द्वारा 19 जून, 1980 में लगा दिया जाने का प्रस्ताव है, उन अधिसूचनाओं की प्रतिक्रिया समाप्ति मार्गपटन पर रख दी जाएगी।

119. अब मैं अपने सम्मानित सहयोगी संचार संघी की ओर से कुछ शब्द कहना चाहूँगा। डाकनार विभाग के कर्मचारियों को मार्गार्थ भत्ते की अद्यायी किए जाने और उनके लिए उत्पादकता में जुड़ा बोनस मंजूर किए जाने के परिणामस्वरूप विभाग का कार्यवालन व्यय काफी बढ़ गया है। हमलिए कुछ भुग्ती दुई सेवाओं की शक्ति दरों को बढ़ाना ज़रूरी हो गया है। इन शुल्क दरों में संशोधन करने के प्रस्ताव करने से समय सरकार बड़ी माध्यमी रूप से ऐसी सेवाओं की शुल्क-दरों में संशोधन करने से दूर रही है, जिनका माध्यम द्वारा इस्तेमाल किया जाना है। पोस्ट काई और अन्तर्वेषीय पदों की कीमतों में कोई बढ़िया नहीं की जाएगी ऐसिन न्यूनम खण्ड पर पदों की शुल्क-दर 30 पैसे से बढ़ा कर 35 पैसे की जा रही है। प्रत्येक 500 ग्राम के लिए पासेल की दर 1.50 रुपये से बढ़ाकर 2.00 रुपये कर दी जाएगी। टेलीफोन कनेक्शन लगाने और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेजाने के प्रभार भी बढ़ाए जा रहे हैं। एक निमाही में 5,000 स्थानीय कालों में अधिक कालों पर मोजूदा 40 पैसे प्रति काल की दर के बजाए 50 पैसे प्रति काल के हिसाब में प्रभार लिया जाएगा। बजट पदों के माध्य एक जापन परिचालित किया जा रहा है जिसमें प्रस्तावित शुल्क दरों का विवरण दिया गया है। इस जापन को देखने से पहले चलेगा कि डाक और दूर संचार की अधिकातर सेवाओं के प्रभारों को घुटा तक भी नहीं गया है। प्रभारों में वे परिवर्तन संभव द्वारा वित्त विधेयक पारित कर दिया जाने के बाद अधिसूचित की जाने वाली सारी बांध में लागू होंगे। प्रस्तावित शुल्क-दर संजोशनों से प्रति वर्ष 27.10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है। वर्ष 1980-81 में लगभग 13 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व का अनुमान लगाया गया है और डाकनार विभाग का राजस्व अनुमान लगाने समय इसे हिसाब में भी लिया गया है।

120. बजट में प्रस्तावित राहतों को हिसाब में लेने के बाबत, कुल मिलाकर करन-प्रस्तावों से जाते वर्ष में, लगभग 283 करोड़ रुपए की निवाल प्राप्ति होगी जिसमें से 223 करोड़ रुपए केन्द्र की मिलेंगे। इस प्रकार बजट में 1417 करोड़ रुपए का धारा रहेगा जिसे मैं बिना कोई व्यवस्था किए छोड़ देना चाहता हूं। यह धारा पिछले वर्ष के धारे के आधे में थोड़ा-भी अधिक है। मेरे विचार में इनसे धारे का अर्थ व्यवस्था पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि मानसून की स्थिति सामान्य रही और यदि हम उन ठोस अधिक नीतियों पर बगवार ग्रामल करें, तो जो हमने पहले ही शुल्क कर रखी हैं, तो हमें इस बात की पूरी आशा है कि कृषि और औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त सुधार होगा जिससे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उल्लेखनीय बढ़िया होगी। साथ ही हम एक दायित्वपूर्ण मूदानीति पर अग्रल करेंगे जिससे अनुनादक या अटेवाजी के प्रयोजनों के लिए बैक अड्डों के विस्तार पर नियंत्रण रखा जा सकेगा।

121. महोदय, बर्तमान सरकार को विवासत में मिली कठिन प्रायिक स्थिति की मजबूतियों के बायरे में रहने हुए, मैंने उन लोगों को राहत देने की भरपुर कोशिश की है जिन्हें उम्री सब से ज्यादा ज़रूरत थी। लेकिन राहतें तो पीछा को कुछ तक नक्की कर सकती हैं और निर्धन समाज की बासिक अवस्थकता तो विकास ही है, इसलिए मैंने पूरी निवेश को उचित प्रोत्तमाहन प्रदान करने का प्रयास किया है। सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों ज्ञेयों में अधिक पूर्जी-निवेश के द्वारा और ब्रांस तौर से विविध भागों में उम्रके बटवारे से उत्पादन और रोजगार दोनों में काफी बढ़िया होनी चाहिए। सरकार की विशेष जिम्मेदारी समाज के उन कमज़ोर बांगों के प्रति है जिन्होंने बड़े उत्पाद के साथ उपनाम प्रदान किया है। इस बजट में, इनके कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयोजन से तैयार किए गए विशेष कार्यक्रमों के द्वारा उनको संभवण देने का प्रयास किया गया है। हमारा दृढ़ संकल्प है कि आयिक स्थिति बहिर किन्तु भी कठिन स्थितीयों न हो जाएं परन्तु ब्रांसक बनाए गई सार्वजनिक वित्तरण प्रणाली के त्रिपुणि नियंत्रण द्वारा पूरा करने के लिए जाएं।

देश में एक मजबूत और एकेजट होकर काम करने वाली गरकार के आ जाने भी मौजूदा उत्पादन क्षमता का पूरा पूरा उपयोग हो सकेगा।

122. देश की अर्थव्यवस्था को स्थायित्व, विकास और सामाजिक न्याय के पथ पर पुनः अग्रसर करने की प्रक्रिया में भेद बजट एक विनाश गोलंदाज है। लेकिन इसकी सकलता उन सभी लोगों के गहरों पर निर्भर करती है जो खेतों-खनियां, मिलों-कारखानों, बिजलीधरों, बदलाहों, रेलों और कोयला खानों आदि विभिन्न धरों से काम करते हैं। इस देश की जनता को इन उद्देश्यों का पूरा करने में यत्नमान मरकार की सकलता के बारे में बड़ी आशाएँ हैं और मूँह पूँह विश्वास है कि वे इस कार्य में सच्चे मन से अपना पूँण ममर्तन प्रदान करने के लिए सदा तप्त रहेंगे। हम सब का यह समान प्रयास होना चाहिए कि हम दलगढ़ पूर्वशहरी और भावाविहारी से ऊपर उठ कर जन-उत्साह का विकास कार्यों के लिए उपयोग करें।

प्र० सी० निवारी, संयुक्त मंत्रिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Budget Division)

Budget 1980-81

SPEECH OF

MINISTER OF FINANCE

New Delhi, the 18th June, 1980

No. M of F (DEA) u. o. No. F. 15(1)-B(D)/80.

(PART 'A')

Sir,

I rise to present the regular Budget for the year 1980-81.

2. Presenting the interim Budget in March this year I gave an account of the poor shape of our national economy and the magnitude of the task facing the nation. The Economic Survey presented to the House last week confirms the brief review made by me in March. As it gives a detailed account of the present condition of the Indian economy and its problems and prospects, I shall content myself with highlighting only a few aspects in order to give the House an idea of the gravity of the economic problems faced by this Government, the action it has taken so far to solve them and the need for other measures some of which I shall outline in the course of this speech.

3. The most important and disconcerting fact about the Indian economy is that the gross national product declined in 1979-80 by about 3 per cent. A fall in agricultural production of about 10 per cent and a reduction of about one per cent in industrial production were responsible for this outcome. The set-back in agriculture was partly on account of the severe drought which affected large parts of the country. The decline in industrial production was mainly the result of a serious deterioration in the infrastructure.

4. The performance of power, coal and railway sectors was one of the most serious deficiencies on the economic scene. No doubt the drought was responsible for a decline of 2.2 per cent in hydel production but what stands out is the inability to meet increased demand through increased thermal generation despite substantial additions made to generating capacity in the past three years. Inadequate supply of coal and its poor quality, poor maintenance, equipment damage resulting in increasing planned and unplanned outages and poor management were responsible for the decline in the percentage of thermal capacity utilisation to as low as 45 per cent.

5. In coal again it was the same story. Despite massive investments the production of coal and lignite in 1979-80 was just 106 million tonnes, marginally better than the level

reached four years ago. The poor performance of DVC and the failure to maintain law and order in the coal mining areas of Bihar and Bengal contributed to the set-back in coal production. At the same time coal could not be transported to thermal stations in adequate quantities because of difficulties in railway movement.

6. In 1979-80 the revenue earning traffic of the Railways in terms of tonnes originating declined by 3.3 per cent from the level reached in 1978-79. The performance of the Railways in terms of tonnes originating of revenue earning traffic has been declining continuously since the peak reached in 1976-77. The deficiencies in the three sectors, power, coal and railways, reinforced one another and inflicted severe damage on the national economy.

7. With the serious deficiencies in infrastructure it was not surprising that there was a fall in the production of major commodities like steel, cement, non-electrical machinery, aluminium and other non ferrous metals and cotton textiles. Sugar production also fell by 28 per cent. There was a decline in capacity utilisation in industry in general.

8. In a situation in which aggregate supply dropped sharply, there was a steep rise in prices. In the fiscal year 1979-80 prices rose by 20 per cent. In some commodities like sugar, gur, khandsari, oilseeds and edible oils the rise was particularly steep. There was also a persistent upward trend in a wide range of manufactures and intermediates owing to the low level of production. The direct and indirect effects of the increases in the prices of crude oil and oil products also contributed to the inflationary pressures in the economy as also the long delayed adjustments in administered prices of commodities like coal and steel. This naturally gave rise to speculative expectations and the liquidity in the system due to large expansion of money supply in the previous years aggravated the price situation.

9. The other area in which there was a deterioration following from all these factors was the balance of payments. It is true that our overall foreign exchange reserves declined by only Rs. 56 crores in 1979-80 but the trend in the various forces operating on the balance of payments has been reversed perceptibly. Export growth in value terms has only been 8 per cent or so which means there was hardly any growth in terms of volume as world inflation has proceeded at about 10 per cent in 1979-80. On the other hand imports have increased by about 25 per cent principally on account of increased oil bill because of a steep rise in the prices of oil and oil products and the consequential impact on other imports such as fertilizer. The result is that the trade gap in 1979-80 was Rs. 2232 crores, double the size of the trade deficit in 1978-79. This has led to a deficit on the current account. The rate of growth of remittances which has in the recent past turned the trade deficit into a surplus on current account also decelerated in 1979-80.

10. Such a dismal economic situation was to a large extent the result of the policies—or should I say lack of policies—of the previous Government. For instance, vacillations in sugar policy contributed to a fall in the area under sugarcane, decline in sugar production and the frittering away of large stocks of sugar carried over from previous seasons through releases which could not be sustained over a period. Had they pursued a more responsible policy on sugar, we would not have been in the unenviable position of having to import sugar for domestic consumption.

11. In infrastructure the lack of coordinated policy in the three sectors of coal, transport and power was responsible for their unsatisfactory performance. The large Budget deficit of Rs. 2700 crores in an economy flush with liquidity and a policy of sweeping taxation on articles of common consumption in a situation of declining production were responsible for the spurt in prices. Finally, the lack of adequate emphasis on export promotion was partially responsible for the reversal of the trend in our balance of payments.

12. What is important now is to devise ways and means to arrest the deterioration and set the economy on the path of stability and growth. The fact that we have a Government which enjoys the confidence of the people and is

decisive should make a qualitative difference; as also the fact that there will be much greater cooperation between the Centre and the States, now that our party has been so enthusiastically returned in the State elections. At the end of May, 1980, we still have food stocks of about 18 million tonnes owing to our earlier foresight. Foreign exchange reserves stood at Rs. 4890 crores as on May 30, 1980. These elements of strength will be effectively utilised to improve the situation. But the House should realise that the magnitude and complexity of the problems we have inherited do not admit of quick and easy solutions. However, the problems are so urgent that we shall tackle them with determination and with the cooperation of all sections of our people.

13. Since it came to power this Government has taken a number of steps to correct the deficiencies in the economic system. Since restoration of infrastructure brooked no delay Government constituted a Cabinet Committee on infrastructure under my Chairmanship to monitor the situation continuously. As power shortages have been an impediment to the growth of production the Committee has devoted a good deal of attention to rectifying the power situation. The Committee wanted to ensure that thermal generation did not suffer for lack of coal and, therefore, decided to make more wagons available for loading coal to thermal stations. As a result the number of wagons loaded daily with coal for thermal stations has gone up from 2900 in January to 3200 in May, 1980.

14. Coastal shipping has been revived to supplement movement of coal by rail and is expected to achieve progressively a target of one lakh tonnes per month to meet the needs of western and southern regions.

15. Due to a number of steps taken coal production increased by 9.4 lakh tonnes in April, and 10.4 lakh tonnes in May, 1980 as compared with April and May, 1979.

16. There has been a dramatic improvement in the port situation. The number of ships waiting for a berth in Bombay, Calcutta and Madras has come down sharply by May, 1980. A good indicator of the improvement in port conditions is the removal of the congestion surcharge for major ports including Bombay and Calcutta from April 1980.

17. As the rainfall during the period October, 1979 to May, 1980 was also deficient causing drought conditions to continue in many States affecting 220 million population, the present Government, immediately after assuming office, mounted relief operations on a massive scale. Central teams were deputed to these and other States and an allocation of Rs. 150 crores was made for drought relief. More than 10 lakh destitutes were provided free food. In addition, about 65 lakh persons were employed daily under the special Food for Work Programme. Government has decided to continue this programme till the end of September, 1980. The existing subsidy on agricultural inputs, including nitrogenous fertilizers, to small and marginal farmers in the mono-cropped drought affected areas where no rabi crops could be grown has also been extended till the end of March, 1981.

18. A 12-point programme of drought management which provides the basic framework and approach for fighting the drought has been evolved and recommended to the States. A large number of rigs have been deployed for sinking wells and a significant percentage of wells bored has proved successful. These steps are expected to bring about permanent improvements in availability of drinking water in the drought affected States.

19. The demand for petroleum products, particularly diesel, increased during the last few months owing to a number of circumstances including the drought. The problem was compounded by almost total cessation of supplies from January onwards from the four refineries dependent on Assam crude which between them normally produce around 350,000 tonnes of petroleum products per month. The situation was tackled with the utmost vigour. Firstly, the maximum quantities of diesel and kerosene were imported between January and April, 1980. 6.2 lakh tonnes of kerosene and 1.1 million tonnes of diesel oil were imported as compared with 4.7 lakh tonnes and 4.8 lakh tonnes respectively in January-April

1979. Secondly, the movement of these commodities was speeded up by all available means. The result has been an increase in the level of supplies amounting to 10 per cent compared with the corresponding months in 1979 and avoidance of a possible adverse effect on rabi production due to a diesel shortage.

20. With regard to prices Government has taken a number of important steps. The coverage of the public distribution system has been widened. With regard to edible oils not only has Government undertaken adequate imports but it has also made arrangements to see that a sizeable portion of these imports go into direct consumption. It is hoped that about 3 lakh tonnes of imported oil will go into direct consumption through the public distribution system and cooperatives. In sugar, Government has activated the disrupted dual pricing system.

21. In keeping with our developmental thrust towards the poorest, the banks have been asked to ensure that a significant proportion of the enlarged priority sector credit will flow to the beneficiaries of the 20-Point Economic Programme, which is being revitalised. To further strengthen the linkage between block level development activities and the banks' credit programmes, the banks have been asked to open by the end of the year, branches at all unbanked block headquarters.

22. Hon'ble Members are aware of the critical role played by our exports in our developmental effort. Therefore, the Government had, over the years, endeavoured to provide all facilities and full encouragement to export promotion efforts. The management of credit and investment finance for export promotion in an increasingly competitive international market is, however, becoming more and more complex. There is thus a need for a specialised institution which will become a focal point for all aspects of export credit and which will devote concentrated attention to the needs of the exporting community. Government has, accordingly, decided to set up an Export-Import Bank, to assist the financing of our international trade. We hope this specialised institution will give the desired boost to our export promotion efforts.

23. In the light of the problems currently facing the economy the tasks to be accomplished are clear enough. As there is a great deal of inflationary potential in the economy, the prime objective of our policy will be to achieve price stability. This will have to be done through an increase in aggregate supply and a moderation of aggregate demand. Therefore, we intend to continue our efforts to improve the working of the infrastructure and to augment available facilities with investment wherever necessary. Secondly, the accent will be on utilising existing capacity more effectively, without slackening efforts to increase capacity, to augment supplies of vital commodities like steel, cement, aluminium and fertilizers. This will simultaneously increase production and employment, reduce the need for imports and benefit revenue.

24. With regard to demand management, we shall have to pursue a policy of linking bank credit expansion to productive and priority purposes and check the diversion of funds to speculative ends. We will also have to pursue an interest rate policy which will help in the abatement of inflationary pressures without hurting productive activity. At the same time profiteers and hoarders intent on exploiting current shortages for personal gain will have to be dealt with sternly. Smuggling will have to be countered through Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act and other means.

25. Since there is a great deal of liquidity in the system, there is an obvious need to minimise the growth of money supply by keeping the budget deficit at a much lower level than in 1979-80. This will require a fiscal policy which will reduce wasteful and unnecessary expenditure, invest resources in increasing the economy's production potential and maximise the revenue potential of the existing tax system.

26. In view of the deterioration in our balance of payments we will have to emphasise the promotion of exports to a far greater extent than has been done in the past three years. At the same time, it is necessary to minimise the growth of imports through a much more energetic policy for augmenting domestic production in areas like edible oils, steel, cement, fertilizers, oil and oil products.

27. Government also intends to pursue policies which will encourage savings and investment in the economy. Since 1971, a convertibility clause is being inserted in agreements governing financial assistance to industrial units by public financial institutions. It has been repeatedly represented by industry that the rigours of the convertibility clause are inhibiting investment. Government has carefully considered the matter and has decided that the policy guidelines for insertion of the convertibility clause be modified on the following lines:—

- (a) The mandatory insertion of convertibility clause will in future apply to financial assistance exceeding Rs. 1 crore instead of Rs. 50 lakhs prescribed at present.
- (b) The financial institutions should hereafter exercise the conversion option in such a way that they do not acquire more than 40 per cent of the share capital of an existing concern. However, in case of persistent default in repayment of loans or mismanagement of an assisted company or continuous closure of an industrial unit of a company producing goods and services essential to the community, the financial institutions might, with the concurrence of Government, exercise their conversion option in such a way that their share-holding can go up to 51 per cent or above.
- (c) Under the existing soft loan scheme for modernisation of jute, cotton textiles, cement, sugar and certain engineering industries, no convertibility clause is being inserted at present. This exemption is being extended to assistance for modernisation in any industry and for rehabilitation of sick units.

Government hopes that these policy changes would remove the present inhibition and encourage fresh investment in and modernisation of industry.

THE PLAN AND BUDGET ESTIMATES FOR 1980-81

28. In our preoccupation with the immediate problems of economic management we should not lose sight of the need to build up the growth potential of the economy over the medium term. If we do not do so, the short term difficulties will only grow further. The reconstituted Planning Commission will present the new programmes and priorities when the Plan is formulated by the end of this year. But meanwhile a Plan for the year 1980-81 has been formulated which will be dovetailed into the Sixth Plan later. The broad objective of the Plan would be to achieve a higher growth rate of 5 per cent per annum.

29. The annual Plan for 1980-81 seeks to revive and restore the health of the economy and accelerate the pace of growth and employment generation. Though the priorities laid down by the earlier Government are not acceptable to us, we have recognised that on-going projects should be fully provided for. Within the room for manoeuvrability permitted by this consideration, we have effected changes in plan provisions or provided for new programmes so as to give a reorientation to the Plan in the desired direction.

30. The new Planning Commission has made a quick review of Plan programmes and priorities. I am glad to announce that in the light of this review the annual Plan outlay for 1980-81 of the Centre is being raised to Rs. 7,340 crores, an increase of Rs. 767 crores over the outlay in the interim Budget; compared with last year's original outlay it is higher by 14.5 per cent. It will be financed by a budgetary provision of Rs. 5,322 crores and internal and other resources of public sector undertakings of Rs. 2,018 crores. A provision of Rs. 3,094 crores has been made for central assistance to the outlay on States' Plans, Union territories' Plans and sub-plans of hills and tribal areas, special component plans for the scheduled castes, schemes of the North Eastern Council, Rural Electrification Corporation and natural calamities. Inclusive of their own resources their Plan outlay will be Rs. 7,253 crores as against an outlay of Rs. 6,099 crores in 1979-80. Altogether the total Plan outlay of the Centre, States, Union territories, schemes of North Eastern Council etc., would amount to Rs. 14,593 crores in 1980-81 as compared with Rs. 12,511 crores in 1979-80—a step up of 16.6 per cent.

31. It is this Government's firm belief that economic growth could be accelerated and its fruits widely shared only if employment opportunities in rural areas are significantly augmented. Development will have no meaning to the vast majority of our people if the poor in the rural areas are not able to secure a livelihood through satisfactory productive work. As an integral part of the new Plan, we have therefore, decided to launch a massive National Rural Employment Programme based on a strategy which will seek to blend opportunities for self-help and optimum utilisation of available local resources. Such a programme will go a long way towards revitalising the rural economy and developing the infrastructure facilities so essential to the life of the community.

32. The Food for Work Programme initiated by us in 1977 has an important part to play in this regard. But in the last two years this programme has displayed certain cardinal weaknesses. In many cases, no attempts have been made to develop an inventory of projects which will meet not only the local needs but also fit in with the overall national priorities.

There was also no firm indication of annual allocation of foodgrains. The programme thus in effect continued on an ad hoc basis. No arrangements were also made for financing the cash component of the works programme undertaken by the State Governments with the help of foodgrains allocated to them. The result was that they could not undertake works which could have led to the creation of durable assets and the building up of productive potential of the areas concerned.

33. In the new National Rural Employment Programme, States will receive assistance not only in the form of foodgrains but also cash assistance so as to enable them to undertake truly productive works of lasting benefit. The Budget estimates which have been presented to the House provide Rs. 340 crores in 1980-81 for this programme. It is estimated that the programme, if properly implemented, could generate 850 to 900 million man days of additional employment. Some part of the provision for this scheme would be specifically earmarked for high priority programmes like social forestry, fuel plantation, rural community housing and water supply and nutrition. Rs. 10 crores have been provided for the Food for Nutrition Programme.

34. The process of economic growth will be incomplete unless the benefits of such growth reach the weakest sections of society. Therefore, the improvement of the socio-economic conditions of the scheduled castes should be a major element of our strategy of development. Comprehensive special component plans for the scheduled castes will have to be drawn up with the objective of earmarking outlays in all relevant sectors in proportion to the scheduled caste population in each State. Such outlays are to be utilised for helping the scheduled caste families to acquire income generating assets and relevant skills for the betterment of their living conditions. The Budget breaks new ground by providing for a special central assistance of Rs. 100 crores to the States to act as a catalyst in the generation of more funds from other sources including financial institutions. This will enable the authorities to provide as a package all the inputs needed in an integrated programme of promotions of the socio-economic condition of scheduled castes.

35. A provision for Central assistance of Rs. 70 crores has been made for the development of tribal people and areas under the Tribal sub-plan. Additional pockets with a population of 10,000 and having at least 50 per cent tribal concentration will be identified, thus bringing nearly 75 per cent of the tribal population in eighteen States and Union territories within the Tribal sub-plan. Greater emphasis will be laid on selected programmes which can benefit the tribal families.

36. A provision of about Rs. 50 crores has been made in the annual Plan for 1980-81 for providing house sites for the landless and weaker sections as part of the 20-Point Economic Programme. The Rural Housing-cum-Hut Construction Scheme for landless workers being operated under the revised Minimum Needs Programme provides not only house sites but also assistance for the construction of huts. This provision will be supplemented under the National Rural Employment Programme which will cover community housing projects in rural areas. Nearly 8 lakh landless families are expected to benefit under this scheme.

37. Since India lives in its villages and nearly 70 per cent of its population derives its livelihood from agriculture, the prosperity of the country depends upon the modernisation of agriculture. The year 1979-80 is a grim reminder of the importance of the performance of agriculture to the development of the Indian economy. The Plan outlay on agriculture and rural development in the current year is being increased to Rs. 2,247 crores from Rs. 1,811 crores in 1979-80. This includes the provision in the Central Plan of Rs. 158 crores for Small Farmers Development Agency, Drought Prone Areas Programme, Integrated Rural Development Programme etc.; Rs. 32 crores for better exploitation of inland and marine fish potential; Rs. 54 crores for Operation Flood II Project; Rs. 59 crores for schemes of agricultural research and education oriented towards improving agricultural productivity through better seeds, better agronomic practices, better water management and better use of fertilizers and other essential inputs; and Rs. 10 crores to increase the production of oilseeds to reach a target of 12 million tonnes.

38. The current levels of international prices of oil and oil products have highlighted the importance of other fuels. Forests can play an important part in providing one such fuel. As forests in India have suffered fast destruction by people in their search for fuel, it is essential that people's participation in the development of forest is secured on an urgent basis. Social forestry in villages will besides meeting the energy requirements of the people also provide additional employment. The raising of fuel and fodder is proposed to be made a part of Minimum Needs Programme and it will receive high priority in the National Rural Employment Programme.

39. We have to press on with the task of increasing the area under irrigation to avoid fluctuations in production and to increase productivity. Therefore, the outlay on major and medium irrigation projects including flood control for 1980-81 is being stepped up to Rs. 1380 crores from Rs. 1258 crores last year. The minor irrigation programme would continue to receive special attention and an outlay of Rs. 266 crores has been made for this purpose. This provision will be supplemented by large financial support from the Agricultural Refinance and Development Corporation. The additional irrigation potential resulting from all this expenditure is expected to be 2.5 million hectares.

40. Clean and safe drinking water is essential for improvement of the quality of life in rural areas. The Central Plan for 1980-81 provides an outlay of Rs. 100 crores as against Rs. 80 crores in 1979-80. Inclusive of the provisions in the States' Plans, a total sum of Rs. 294 crores will be available for this vital programme. It is expected that by the end of the current year 35,000 additional villages identified as problem villages will be having protected water supply arrangements. A part of the outlay has been earmarked for rigs to be supplied to States for boring wells in drought affected areas. An additional sum of about Rs. 40 crores has been allocated in the current year to the drought affected States to take up new water supply schemes and complete those already in hand.

41. The khadi, village and small scale industries sector has the highest employment potential next to agriculture. The outlay on this sector in the current year will be Rs. 150 crores and additional production during the year is estimated at Rs. 146 crores. The House will recall that the 20-Point Economic Programme has particularly emphasised the development of the handloom sector in this context. In pursuance of this objective, we propose to set up a national level Handloom Development Corporation for providing a package of marketing and developmental assistance for the handloom industry. Provision has also been made for establishing an Institute of Handloom Technology in the North-Eastern region, which is well known for its exquisite handloom products.

42. The provision for the power sector has been raised by over 11 per cent i.e., from Rs. 2466 crores in 1979-80 to Rs. 2745 crores. The work on the four Super thermal power stations in the different regions of the country is being accelerated. Total outlay on the rural electrification programme will be Rs. 285 crores in 1980-81. The target in 1980-81 is the energisation of 4 lakh pumpsets and the electrification of 25,000 villages.

311 GI/80--3

43. Similarly, an outlay of Rs. 473 crores is being provided in 1980-81 as against Rs. 364 crores last year for improving the production of coal (including lignite). This includes a provision of Rs. 92 crores for the Neyveli Lignite Corporation. The bulk of this allocation is for the second mine project which will produce 4.5 million tonnes per annum and the second thermal power station with a generating capacity of 630 MW. A production target of 113.5 million tonnes has been set for coal for the current year as against the actual production of 106 million tonnes in 1979-80.

44. In view of the impact on the balance of payments of the rising prices of oil there can be no two opinions about the urgency of developing our own oil resources. The Plan outlay for the petroleum sector for 1980-81 is Rs. 837 crores, Rs. 215 crores more than the outlay last year. The Budget provides only Rs. 99 crores out of this. This outlay is for the completion of facilities for Phase III development of Bombay High and advance action in regard to Phase IV so as to build up a production capacity of 12 million tonnes per year. It also includes the expenditure required for the development of the South Bassein Gas field and the gas pipeline to the new fertilizer projects. On-shore exploratory drilling in the eastern region is to be intensified in view of the region's higher potential for hydro carbon discoveries.

45. The Central Plan outlay on chemicals and fertilizers is being raised to Rs. 319 crores in 1980-81 to provide adequately for new gas-based fertilizer plants in Maharashtra and Assam. In addition, a provision of Rs. 20 crores has been made for fertilizer projects in the cooperative sector.

46. The Central Plan also provides in the current year an outlay of Rs. 803 crores for the steel sector as against Rs. 600 crores last year. The outlay includes a provision of Rs. 200 crores for raising the capacity of the Bokaro Steel Plant to four million tonnes per annum and an outlay of Rs. 190 crores for the Bhilai Steel Plant for a similar expansion. Work on the Salem Project will proceed at the required pace with an outlay of Rs. 57 crores. A substantial beginning will be made on the new Visakhapatnam Steel Plant with a provision of Rs. 70 crores. The target of saleable steel in the current year has been fixed at 8.76 million tonnes as against the anticipated production of 7.22 million tonnes in 1979-80.

47. An outlay of Rs. 130 crores is being made in 1980-81 for the mines sector. This includes a provision of Rs. 10 crores for the new east coast aluminium project, Rs. 28 crores for the Malanjkhand Copper Project and Rs. 19 crores for the intensification of the activities of the Geological Survey of India and the Mineral Exploration Corporation.

48. A provision of Rs. 64 crores has been made for BHEL for its continuing schemes and for the production of large size turbo generators at Hardwar and the expansion of boiler manufacturing capacity at Tiruchy.

49. Since port congestion also has figured prominently as a constraint till recently, a provision of Rs. 102 crores is being made in 1980-81 for developing major and minor ports. However, only a sum of Rs. 60 crores has been provided in the Budget as the rest of the expenditure is being met from internal resources of the Port Trusts. Bombay, Madras and Cochin are being equipped to handle the anticipated increase in container traffic. A beginning has been made on the integrated development of Cochin port.

50. The Plan outlay for 1980-81 for the Posts & Telegraphs Department is Rs. 415 crores. It is proposed to provide additional 1.75 lakh lines switching capacity and 1.7 lakh direct exchange lines and other facilities. The number of post offices in rural, backward and hilly areas is also proposed to be increased. The norms for providing telegraph and telephone facilities in tribal areas have been further liberalised to cover areas having a population of 2500 in a group of villages within a radius of 10 kms. Provision has also been made for the expansion of manufacturing capacity for switching equipment.

51. Family Planning programme suffered a serious set back in the past three years. A revitalisation of this programme must constitute an important element of the new Five Year Plan. If an improvement of the living conditions of our people is our goal, a provision of Rs. 250 crores is being made in 1980-81 for health and family welfare. Of this, Rs. 140

crores will be for family welfare. The emphasis in the family welfare programme will be on educating the people about the desirability of a small family and providing the necessary technical services on an adequate scale. An attempt will also be made to provide improved health services in rural areas, eradicate communicable disease, and provide health education.

52. The development problems of a poor society of 650 million people are bound to be spurious. For a solution of these, within a reasonable time, it will be necessary to harness the forces of science and technology. India is favourably placed with regard to the development of science and technology in that she has a large pool of scientific and technical man-power and a vast institutional infrastructure developed over the last thirty years. While our scientific institutions can help to advance the frontiers of knowledge, it is science based technology which can help to raise production and productivity. Therefore, an outlay of Rs. 116 crores has been provided in the Central Plan for 1980-81 for science and technology.

53. I will now make a brief mention of a few changes in the non-Plan expenditure. The provision for Defence expenditure is Rs. 3600 crores, Rs. 300 crores more than the provision made in the Interim Budget. The provision for export subsidy has been increased from Rs. 330 crores to Rs. 355 crores, in view of the need for a larger export effort.

54. Loans to State Governments, as their share of small savings collections, are being stepped up from Rs. 650 crores in the interim Budget to Rs. 715 crores, in view of the anticipated improvement in these collections. Short term loans to State Governments for agricultural inputs are also being increased by Rs. 50 crores. Besides additional provision has been become necessary to meet unavoidable commitments like additional dearness allowance to Central Government employees, purchase of heavy water for atomic power plants, etc. However, the above increase in non-plan expenditure will be partially offset by reduction in fertilizer subsidy.

55. The Constitution envisages provision of free legal aid by Government in order to ensure that an opportunity for securing justice is not denied to any citizen because of economic or other disabilities. The concept of legal aid has also been dealt with by a Committee on Juridicare headed by Justice P. N. Bhagwati, whose Report dated 31st August, 1977 has been laid before Parliament. Several States have been attempting legal aid programmes. It is proposed to co-ordinate these schemes and also initiate suitable schemes at the Centre after an examination of the various aspects. A committee for guiding the legal aid schemes and implementing the same is being constituted with a Supreme Court Judge as its Chairman. The Budget for 1980-81 makes a provision for this purpose.

56. Taking into account the effect of the above and some other changes, the total non-Plan expenditure is now estimated at Rs. 13,051 crores as against Rs. 12,822 crores in the interim Budget.

57. As regards receipts in the current year, at existing levels of taxation Corporation tax is estimated to yield Rs. 11 crore more than what was reflected in the interim Budget; this improvement is mainly based on the actual trends of collection in 1979-80. On the basis of latest available data on estimated levels of imports and production during the current year, Customs duties and Union Excise duties are also expected to yield Rs. 40 crores and Rs. 108 crores respectively more than anticipated in the interim Budget. However, these increases will be more or less offset by the recent decision of Government to withdraw customs and excise duties on fertilizers. Taking into account States' share of taxes net tax revenue at existing rates of taxation is estimated at Rs. 8723 crores as against Rs. 8725 crores in the interim Budget.

58. On the basis of the latest indications available external assistance, net of repayments, in 1980-81 is estimated at Rs. 1252 crores showing an increase of Rs. 56 crores over the figures included in the interim Budget. In addition we expect to avail of a loan of Rs. 540 crores from the Trust Fund of the International Monetary Fund in 1980-81 and the Budget assumes credit for this.

59. There is a welcome increase in small savings collections. The estimate for 1980-81 is now placed at Rs. 1100 crores as against Rs. 1000 crores in the Interim Budget. Of the in-

crease of Rs. 100 crores, I.e. 65 crores will accrue to the States as their share.

60. It has been decided that a part of the investible resources of Life Insurance Corporation, General Insurance Corporation, and Unit Trust of India should be lodged with Government in Special deposit accounts to augment resources for financing the Plan. Budget for 1980-81 takes a credit of Rs. 100 crores on account of these deposits.

61. When we are seeking to step up investment in public sector, it is necessary to adopt an innovative approach to the problem of mobilising resources for sustaining such investment. As Hon'ble Members know, private sector companies raise resources in the form of deposits from the public. Government feels that there is no reason why public sector companies with competent professional management should not do so. Accordingly, we have decided to allow selected public sector units to raise public deposits on the same lines as the companies in the private sector. When this scheme makes headway, dependence of these public sector enterprises on budgetary support will get reduced. But I have refrained from taking credit for such relief at this stage.

62. Taking into account other variations and also the effect of the changes in the fare and freight rates of Railways and of changes in Posts and Telegraphs tariff, to which I will refer a little later, the total receipts in 1980-81 are estimated at Rs. 19,827 crores as against Rs. 18,980 crores in the interim Budget. Total expenditure is estimated at Rs. 21,467 crores. The deficit at existing rates of taxes will thus be Rs. 1640 crores.

PART B

63. I now turn to my proposals in the field of direct taxes. In framing these proposals, I have borne in mind certain broad considerations, namely, that the rates of direct taxes should be such as to promote voluntary compliance; that the farmers, workers and the middle class should be afforded some relief in pursuance of the commitment in our Party's manifesto and some stimulus should be provided for raising the level of savings and investment in the national economy. At the same time, a concerted attempt should be made to counter certain widely prevalent devices for tax avoidance through fragmentation of income and wealth.

64. The middle class is among the worst hit by the rise in prices in recent years. As Hon'ble Members are aware, even skilled workers in the organised sector are now liable to income-tax, at the present level of exemption. In order to afford a measure of relief to this class of persons, I propose to raise the exemption limit for income-tax on personal incomes from Rs. 10,000 to Rs. 12,000. With a view to keeping the sacrifice of revenue within manageable limits, the *nil* rate slab of income is being retained at Rs. 8,000. As a result, in cases where the taxable income exceeds Rs. 12,000, the incidence of income-tax, excluding surcharge, will remain at the existing levels, subject to the grant of marginal relief in cases where the taxable income exceeds the exemption limit by a small margin. This proposal will benefit more than six lakhs of income-tax payers.

65. Hon'ble Members will recall that the rates of income-tax on the personal incomes were reduced in 1974 on the basis of a recommendation of the Direct Taxes Enquiry Committee and this process was taken one step further in 1976 when these rates were again lowered. The reduction in rates had largely fulfilled the expectation that it would lead to better tax compliance. Unfortunately, the movement in this direction was reversed under the Janata Government and the rates of income-tax were increased in stages. I am of the view that the position in this regard should be set right. I accordingly propose to reduce the surcharge on personal incomes in the case of all categories on non-corporate tax-payers from 20 per cent to 10 per cent. This will not only bring down the maximum marginal rate of tax from 72 per cent to 66 per cent but will benefit taxpayers in all slabs of income.

66. In view of the somewhat steep rise in prices of assets, I also propose to raise the exemption limit for wealth-tax from Rs. 1 lakh to Rs. 1.5 lakhs with effect from the current assessment year. In cases where the taxable wealth exceeds this limit, the tax burden will, however, be retained at existing levels, subject to the usual marginal relief.

67. Government hopes that these concessions will provide the necessary inducement to the vast majority of our taxpayers for correct declaration of their incomes and wealth.

68. I propose to counter some of the more commonly used devices for tax avoidance.

69. As Hon'ble Members are aware, the separate treatment accorded to Hindu undivided family in tax laws has been widely used for avoidance of proper tax liability. I accordingly propose to de-recognise partial partitions of Hindu undivided families both for income and wealth taxation. Partial partitions made on or after 1st January, 1979 will not be recognised for tax purposes and taxes will continue to be levied on the basis that the existing Hindu undivided family had continued to remain joint.

70. At present, Hindu undivided families having one or more members with independent income exceeding the exemption limit are charged to income-tax at rates which are somewhat higher than those applicable in the case of individuals. In order to further restrict the use of Hindu undivided family for the purposes of tax avoidance, I propose to raise the rates of income-tax in the case of such Hindu undivided families. The maximum marginal rate of 66 per cent will now apply on the slab of income over Rs. 50,000 and the rates on some of the lower slabs will also be raised to somewhat higher levels. With these two changes in regard to tax treatment of Hindu undivided families, I hope that the urge for forming multiple Hindu undivided families merely for fragmentation of income and reduction of tax liability will be weakened.

71. Hon'ble Members will recall that the Government had in 1970 taken several measures to prevent the use of private discretionary trusts as a device for tax avoidance. Experience, however, shows that these measures have not been fully effective and the proliferation of such trusts has not been curbed to the desired extent. I, therefore, propose to tighten the provisions in respect of private trusts. At present, discretionary trusts are taxed at a flat rate of 65 per cent of their income and 1.5 per cent of their wealth, or at the rates applicable in the case of an individual, whichever is higher. Under my proposal, such trusts will be charged to income-tax at the maximum marginal rate and to wealth-tax at the flat rate of 3 per cent or at the appropriate rate applicable in the case of an individual, whichever is higher. I also propose to make several other provisions in relation to taxation of private trusts with a view to plugging some loopholes which have come to the notice of Government. All these provisions will take effect from the current assessment year.

72. Charitable and religious trusts are sometimes used for acquiring or maintaining control over business or industry for private ends. In 1975, we had laid down a pattern for investment of funds of charitable or religious trusts if they were to continue to enjoy the tax exemption. With a view to enabling such trusts to change over to the new pattern of investment in a smooth and gradual manner, the law provided that the new pattern may be adopted before 1st April, 1978. This date was subsequently extended to 1st April, 1981. Such trusts have, therefore, been given ample time to adjust to the new policy. I want to put them on notice that this time limit will not be extended.

73. Our tax laws have always sought to encourage long-term savings through life insurance, provident funds and other similar instruments. Unfortunately, the efficacy of the provisions for encouraging savings was impaired last year when the incentives for savings were drastically reduced. Hon'ble Members should be glad to know that I propose to restore incentives for such savings to the pre-1979 budget levels. The taxpayers will thus be entitled to 100 per cent deduction in respect of the first five thousand rupees of the qualifying savings, 50 per cent in respect of the next five thousand rupees and 40 per cent of the balance.

74. As a further measure for promoting savings in the household sector, I propose to give an option to income-tax payers to retain moneys in their Community Deposit Accounts beyond the due dates on payment of interest at the existing rate applicable to such deposits. Further, I propose to liberalise the tax exemption in respect of interest on balances with recognised provident funds. At present, interest on such funds is exempt from income-tax to the extent it does not

exceed one-third of the salary income of the employee. I propose to remove this ceiling limit.

75. It is essential to promote new investment in industry. At the same time, the fiscal system should not lead to a bias in favour of capital-intensive techniques. Keeping these twin objectives in view, I propose to continue the tax holiday in respect of new industrial undertakings, ships and hotels, but in a modified form. Under my proposal, tax holiday will be available in respect of new industrial undertakings, ships or approved hotels with reference to a specified percentage of the income derived from these sources. In the case of companies, 25 per cent of the profits derived from these sources will be exempt for a period of seven years. In the case of noncorporate taxpayers, the percentage of exempted profits will be 20 per cent. In the case of co-operative societies, the tax holiday will be available for a period of ten years as against seven years in the case of other categories of taxpayers. This concession will be available in the case of all small-scale industrial undertakings which go into production after 31st March, 1981 but before 1st April, 1985, that is, till the end of the new Five-Year Plan period. For other industrial undertakings, the concession will apply only where they do not produce articles or things listed in the Eleventh Schedule to the Income-tax Act. The concession will also be available in the case of approved hotels which start functioning or new ships which are acquired during that period.

76. It is necessary to encourage new investment particularly in view of shortages in several key sectors of the economy. As a special stimulus for new investment, I propose to allow, in the year of installation, an additional depreciation in an amount equal to 50 per cent of the normal depreciation on new machinery or plant installed during the new Plan period. The proposed additional depreciation will not be admissible in respect of ships, aircraft, road transport vehicles, office appliances or machinery or plant installed in office premises or residential accommodation.

77. There is a widespread feeling of frustration among the scientific community. This Government is keenly aware of the contribution which our scientists and technologists can make to the economic regeneration of India and is determined to promote research and development activities in a big way. I, therefore, propose to allow a weighted deduction in an amount equal to 125 per cent of the actual expenditure incurred on scientific research in any in-house R&D facility where such expenditure is incurred on a programme approved by the prescribed authority having regard to the social, economic and industrial needs of India. In addition, I propose to extend the scope of the existing provision for a weighted deduction on the expenditure incurred on scientific research under sponsored programmes in approved laboratories so as to cover the expenditure similarly incurred in in-house R&D facilities of public sector companies. I have no doubt that the Hon'ble Members will welcome these concessions.

78. At present, income-tax payers are required to pay advance tax during the financial year on the basis of their own statements or estimates. Where the estimated advance tax is likely to fall short of the tax on current income by more than 33-1/3 per cent of the estimate, the taxpayers are required to make an upward revision of the estimates. I propose to reduce this margin from 33-1/3 per cent to 20 per cent in the case of companies. There will be no change for other taxpayers. This change will enable us to realise a larger share of the tax due as advance tax and thus have a favourable impact on Government's ways and means position in 1980-81.

79. In order to encourage the employment of blind and handicapped persons in business and industry, I propose to provide for a weighted deduction of one and one-third times the salary paid to such persons by employers where such salary does not exceed twenty thousand rupees in a year. Further, I propose to enhance the deduction currently available in computing the taxable income of blind and handicapped persons from five thousand rupees to ten thousand rupees.

80. At present, standard deduction in computing the salary income is not available in the case of pensioners. With a view to affording some relief to pensioners who are amongst

the worst hit by the rise in price, I propose to extend the benefit of standard deduction in their case as well.

81. In order to encourage our sportsmen to compete in international events, I propose to allow a deduction equal to 25 per cent of their foreign earnings if these are brought into India in foreign exchange. This provision will apply in relation to the current assessment year and onwards. I also propose to allow higher deduction in respect of savings made by sportsmen through life insurance and provident funds etc. as currently available in the case of authors, playwrights, artistes, musicians and actors, sportsmen will thus be entitled to deduct contributions made to life insurance and provident funds up to 40 per cent of their professional income and 30 per cent of the remaining income, subject to a maximum of Rs. 50,000.

82. In 1978, certain restrictions were placed on the deductible amount of expenditure on advertisement, publicity and sales promotion. These restrictions have particularly hit small and medium business. I, therefore, propose to do away with these restrictions.

83. At present, income from poultry and dairy farming and livestock breeding is exempt from Income-tax upto 33-1/3 per cent of such income or ten thousand rupees, whichever is higher. I feel that time has come when persons deriving income from these sources should also contribute a little more to the national exchequer. I accordingly propose to restrict the deduction in respect of such income to one-third of such income or fifteen thousand rupees, whichever is less.

84. At present, agricultural property is included in the taxable wealth for the purposes of the levy of wealth-tax. At the time when agricultural property was brought within the tax net, it was hoped that it would be a potent instrument for mobilising resources from the affluent section of agriculturists. But our experience of over the last decade has been most disappointing. The amount realised as wealth-tax on agricultural property has generally been less than Rs. 1 crore per annum. The valuation of agricultural land has posed difficulties leading to complaints of harassment. As this tax has clearly failed to achieve its original objective, I propose to discontinue the levy of wealth-tax on agricultural property except in the case of owners of tea, coffee, rubber and cardamom plantations. I am sure that this measure will be widely welcomed by our farmers.

85. I also propose to make certain amendments in the Income-tax Act to counteract certain court decisions which have resulted in unintended benefit to taxpayers. The Finance Bill further contains certain proposals for the amendment of direct taxes which are of minor significance. I will not take the valuable time of the House in explaining the same.

86. The reduction in rates and other concessions in respect of direct taxes should ordinarily involve loss of revenue. However, I am of the view that reduction in rates will lead to significantly improved compliance with tax laws. The legislative amendments made for countering tax avoidance devices and the changes in the provisions in regard to advance tax should result in larger accretion of revenue. On a broad judgement of the overall impact of all the proposals relating to income-tax and wealth-tax, I am not assuming any loss of revenue. I recognise, however, that there may be need for some adjustment in the inter-se shares of Centre and States under Income-tax. Such adjustments will be made in the course of the year in the light of trends in collections.

87. An upward adjustment of lending rates should moderate the inflationary pressures in the economy. I accordingly propose to revive interest-tax in relation to interest earned by scheduled commercial banks after 30th June, 1980. The scope of the levy is being extended to cover also interest received by the larger all-India industrial finance institutions, namely, IDBI, ICICI, IFCI, and IRCL. The tax will be levied at the rate of 7 per cent on the chargeable amount of interest as in the past. This measure will yield Rs. 217 crores in a full year and about Rs. 108.5 crores in the year 1980-81.

88. With a view to checking lavish expenditure incurred on accommodation and entertainment in luxury hotels, I propose to introduce a Bill in the current session to levy a new tax at 15 per cent on gross receipts of hotel, in which the minimum tariff for a single room is 75 rupees per day. The new levy is proposed to be made effective from 1st September,

1980. This will yield about Rs. 12 crore, in a full year and the revenue during 1980-81 will be of the order of crores.

89. I shall now turn to my proposals on indirect taxes. In framing my proposals I have kept in view the following objectives. To the extent additional resource mobilization is inescapable, this should be done in such a way as not to enhance the burden on any commodity significantly. Subject to this consideration, the small scale segment of our industry should be encouraged. Industries with significant employment and export potential should be provided encouragement through suitable adjustment of duty structure. The duty burden on some articles of common consumption should be reduced or totally removed.

90. At the outset I would like to put the Hon'ble Members at ease by pointing out that my proposals are modest. I have tried to avoid the usual device of picking out selected items for new or increased levies at relatively high rates.

91. For this year, I have sought to spread the effect of the additional taxation thinly on a wide range of products, taking care to leave out articles of common consumption. I propose to achieve this objective through the special excise duty which is even now leviable on all excisable goods at 1/20th of the basic excise duty, but from which a number of commodities have been exempted. Under my proposal, the special excise duty will be levied on those items which are at present, exempt from the levy, at the rate of 1/20th of the effective basic excise duty rates applicable. Certain commodities will however, continue to be totally exempt from the levy. Thus there will be no special duty on motor spirit, including naphtha, kerosene, high speed diesel oil, light diesel oil and liquefied petroleum gas or on coal or electricity. Again, the special excise duty will not be levied on matches, or on vanaspati, or on goods falling under Tariff Item 68. Where special excise is already leviable at 1/20th of the effective basic duty, I propose to increase this to 1/10th of the effective basic duty. This increase will not, however, apply to furnace oil, asphalt, bitumen and tar, petroleum products not otherwise specified and calcined petroleum coke. Sugar and processed vegetable non-essential oils will also not be subjected to the increased levy. Cigarettes, which are at present totally exempt from special excise duty will be subjected to special excise duty at 1/10th of the basic excise duty rates. These proposals would yield a revenue of Rs. 197.71 crores in a full year. The impact of these proposals relating to special excise duties will also yield a sum of Rs. 16.75 crores in the shape of countervailing duties on imported goods.

92. Soda ash and caustic soda command a sizable premium in the market on account of persistent shortages. I propose to mop up a part of this premium by raising the excise duty on these products from 10 per cent to 15 per cent ad valorem. I also propose to increase the excise duty on starch from 10 per cent to 15 per cent ad valorem. This step will bring these chemical products on a par with other chemical products which, in general, bear excise duty at 15 per cent ad valorem. Synthetic rubber at present bears duty at the very low level of 5 per cent ad valorem. As a revenue measure, I propose to raise the excise duty on synthetic rubber from 5 per cent to 10 per cent ad valorem. Similarly, the rate of excise duty on specified acids is being raised from 10 per cent to 15 per cent ad valorem. These measures would fetch in a full year, additional revenue of Rs. 18.93 crores.

93. On revenue considerations, I propose to subject molasses to a specific duty of Rs. 30 per metric tonne under a separate Item in the Central Excise Tariff instead of 8 per cent under Item 68 of the Central Excise Tariff as at present. The levy is, however, proposed to be restricted to molasses produced in vacuum pan sugar factories. Molasses produced in khandsari sugar units, which goes inter alia, for edible purposes, is proposed to be exempted. The revenue yield as a result of this proposal is estimated to be Rs. 4.24 crores in a year.

94. I now come to proposals which are designed to provide a higher degree of protection to certain sectors of indigenous industry. The first proposal relates to audio frequency amplifiers, an item reserved for the small scale sector. In view of the adverse effect of imports of this item, I propose to increase the customs duty on imports from 75 per cent to 120 per cent ad valorem. My other proposal relates to imported unexposed colour positive cinematograph films, in respect of which the basic customs duty is proposed to be raised from 50 paise to Re. 1 per linear metre to enable the indigenous

public sector unit to withstand competition from imports. I also propose to increase the countervailing duty on imported computers from 10 per cent to 20 per cent ad valorem as a measure of affording protection to the indigenous computer industry. These measures are designed to yield additional revenue of about Rs. 1.83 crores in a full year.

95. I have only one more revenue proposal in the field of indirect taxes. This relates to passengers' baggage. As Hon'ble Members are aware, baggage allowances were substantially liberalised in 1978 and, for the generality of Indian passengers going abroad for short visits, the allowances consist of Rs. 1,000 worth of duty-free goods and Rs. 2,000 worth of goods on payment of duty. Despite this liberalisation, goods in the nature of baggage continue to be imported by many passengers in quantities substantially higher than the permissible limits. This is mainly due to the prevailing craze for foreign goods and the high margin of profit on the sale of these goods in India. Such cases of import of baggage items in excess of the permissible limits necessitate initiation of adjudication proceedings which generally have the effect of slowing down the tempo of passenger clearance in our international airports. I have given thought to this problem and I am making two proposals in this regard. The first is a pure revenue measure of increasing the effective rate of duty on baggage articles in excess of the free allowances from 120 per cent ad valorem to 150 per cent ad valorem. This measure is to come into force immediately and is expected to yield an additional Rs. 20 crores in a full year. The second measure to be brought into force shortly, provides for the levy of duty at a flat rate of 320 per cent on baggage imported in excess of the permissible limits, that is, in excess of what can be passed free or on a duty of 150 per cent. At present, such articles would be treated as unlicensed imports, resulting in confiscations, fines and penalties designed to wipe out any profit on their sale. The increased rate of duty is intended to replace these fines and penalties, without having to go through the time-consuming process of adjudication. Goods which are obviously in the nature of trade goods will, however, still attract penal action.

96. I have a few other proposals which are essentially in the nature of rationalisation measures. The first one relates to aerated waters. In the interest of simplification, it is proposed to do away with the existing distinction between aerated waters containing caffeine and those not containing caffeine for the purpose of excise duty. Instead, it is proposed to levy on all flavoured aerated waters a uniform duty at 40 per cent ad valorem. The revenue effect of the proposal is expected to be negligible.

97. I have given considerable thought to the problems thrown up as a result of the changes made in the 1979 Budget in the excise duty structure applicable to the match industry. While the duty advantage enjoyed by the cottage sector obviously needs to be maintained, the non-mechanised middle sector should not be allowed to make inroads into the cottage sector. In order to ensure that the benefit of the lower rate of duty accrues only to the genuine cottage sector units, I propose to confine the duty concession to match boxes bearing approved labels and sold to or marketed through the KVIC, State Agencies and registered cooperative societies. At the same time, I do not find justification for the continuance of the existing limits placed on the clearances of matches by the cottage sector at the concessional rate of duty. I, therefore, propose to abolish the existing limit on production by the cottage sector units. I am confident that this package of measures will result in accelerated growth of the cottage sector of the match industry.

98. There have been complaints of malpractices in the biri industry by manufacturers who have been taking advantage of the liberal exemption limit applicable to the unbranded sector which is at present 60 lakhs of biris per manufacturer per year. With a view to reducing the possibilities of malpractices, I propose to lower this exemption limit to 30 lakhs of unbranded biris per manufacturer per year, which will still leave out of the excise net the really small manufacturer and the self employed manufacturer. This is not designed as a revenue measure.

99. Some of the provisions in the Finance Bill are aimed at rationalisation or clearer definition of certain central excise tariff items to remove doubts or difficulties which have come to notice. The details of these measures may be found in the Budget papers.

100. I shall now turn to concessions in the area of indirect taxes. The small manufacturer plays a significant role in our economy. I would like to improve his competitive position vis-a-vis the large manufacturer and thus widen the entrepreneurial base of our economy. Only in this way can we check concentration of economic power. There is already a scheme of excise duty concessions applicable to manufacturers of 70 excisable commodities, under which clearances upto Rs. 5 lakhs in value in a year have been exempted from duty. I now propose to liberalise this concession in two respects. First I propose to include two more groups of commodities under the scheme. These are chemicals, namely, sodium bichromate, bleaching powder, calcium carbide and artificial and synthetic resins and plastic materials. Besides, the coverage is being widened in respect of paper and paper boards. But the second and more important concession which I propose to introduce is that in respect of all the commodities covered by the scheme, clearances between Rs. 5 lakhs and Rs. 15 lakhs will bear only three-fourths of the applicable rate of excise duty as against the normal duty at present. This measure should benefit a large number of small manufacturers. The revenue sacrifice will be of the order of Rs. 6.50 crores in a full year.

101. Last year's Budget made a change which affected a substantial number of small manufacturers of goods falling under the residuary Item 68 of the Central Excise Tariff. Hon'ble Members will recall that the quantum of duty-free clearances was reduced from Rs. 30 lakhs to Rs. 15 lakhs. I had opposed this change then. As a measure of undoing the hardship caused to such small manufacturers, I propose to provide for complete exemption from duty for clearances upto Rs. 30 lakhs per annum. In other words, small manufacturers of goods falling under Item 68 of the Central Excise Tariff, whose capital investment on plant and machinery does not exceed Rs. 10 lakhs, will be eligible for complete exemption from duty on their first clearances of goods upto Rs. 30 lakhs in a financial year provided their clearances during the preceding financial year did not exceed Rs. 30 lakhs. For the remaining part of the current financial year, the quantum of clearances eligible for full exemption from duty will be fixed at a correspondingly lower figure. This concession is expected to cost Rs. 2.4 crores in a full year.

102. Paper and allied products are in short supply in the country and new investment in this sector has not been readily forthcoming. Much can be done by smaller units to help in filling the production gap. To encourage them, I propose to extend a concessional rate of duty of 20 per cent ad valorem as against the present rate of 30 per cent, to paper and paper board produced by small manufacturers whose clearances in the preceding financial year did not exceed 300 tonnes of paper and paper board. This concession will cost a little less than Rs. 1 crore in a full year.

103. The electronics industry has considerable employment and export potential. We have the necessary skills and expertise and these should be harnessed through appropriate fiscal incentives for development of the electronics industry in a big way. This is a field which offers great scope to small scale manufacturers. I am, therefore, proposing some duty concessions in respect of the industry. There will be a reduction in customs duty on specified items of capital goods such as machines and instruments required by the electronics industry and not produced within the country. The customs duty on such items will be reduced from the present levels of duty (which in some cases are as high as 89 per cent ad valorem) to a total of 25 per cent ad valorem. Similarly, I also propose to reduce the customs duty on specified raw materials and components required for the electronics industry from their present levels (which in some cases are higher than 200 per cent ad valorem) to 45 per cent ad valorem plus countervailing duty where an excise duty is leviable under Item 68. These two concessions will cost the exchequer Rs. 4.7 crores in a full year.

104. The experience of other countries shows that the growth of consumer electronics facilitates in due course the development of other sophisticated lines of production in electronics. Television is a powerful medium of communication and education. With a view to enabling a larger number of people to get the benefit of this medium, I propose to reduce the excise duty on cheaper priced T.V. sets from 15 per cent to 10 per cent ad valorem, and to effect a corresponding reduction in the duty on other T.V. sets from 30 per cent to 25 per cent ad valorem. These concessions would entail a revenue sacrifice of Rs. 1.5 crores in a year.

105. Radio is an equally powerful instrument of education and entertainment and is more widely in use. Government considers that single and two band radio sets should be popularised particularly in rural areas. The licence fee on such sets has proved to be irksome and inhibits purchase of radio sets by the rural folk. It is, therefore, proposed to abolish the fee in respect of single and two band radio sets including transistor sets. This measure, which I am sure will be widely welcomed, will cost Government about Rs. 4 crores.

106. Our computer industry is still in its infancy, compared with those of other countries. In order to provide an additional incentive for indigenous production and improvement, I propose to reduce the excise duty on indigenously manufactured computers from 25 per cent to 20 per cent ad valorem.

107. Ship building is a high priority industry and has an important part to play in promoting economic self-reliance. The Indian ship building industry is finding it increasingly difficult to face competition from foreign shipyards. I, therefore, propose to extend full exemption from excise duty to ocean going vessels built in Indian shipyards. This relief would cost about Rs. 5 crores in the current financial year.

108. Hon'ble Members would be aware that Government has been following the practice of bringing down the import duty on selected machinery items having no indigenous angle to 25 per cent ad valorem as a measure of reducing capital costs in industries. Carrying this process further, I propose, this year, to reduce the import duty to 25 per cent ad valorem on twelve more items of capital equipment. These include five items of machinery used in the printing industry, such as High speed Letter press rotary and off-set rotary printing machines, Mono/Lino Type Casting machines etc. These concessions would entail a revenue sacrifice of Rs. 1.84 crores in a full year.

109. The cost of high pressure gas cylinders constitutes a significant portion of the total capital outlay required by the Gas Industry. With a view to reducing, at least in part, this capital outlay, I propose to extend complete exemption from customs duty on steel tubes imported for fabrication of high pressure gas cylinders. I also propose to reduce the excise duty on such cylinders from the existing level of 15 per cent, to 8 per cent ad valorem, which is the duty level applicable under Item 68. These two measures, taken together, are estimated to cost Rs. 1.89 crores in a full year.

110. I have a proposal of general application, which is intended to facilitate manufacturers of excisable goods using inputs on which excise duty is leviable. In order to give relief in such cases, two procedures are in vogue at present. One is what is called the set-off procedure. The other is the proforma credit procedure under rule 56A of the Central Excise Rules. The proforma credit procedure is generally recognised to be more beneficial and less irksome to the manufacturers. I, therefore, propose to replace the existing concessions based on the set-off procedure by similar concessions based on the proforma credit procedure. I am sure that this measure will be welcomed by the industry.

111. It is a little painful for me to remind Hon'ble Members that last year's budget had increased excise duty on a number of articles of common consumption to a significant extent. I propose to reverse this trend. Thus —

- Specified life-saving drugs, 30 in number, will be fully exempted from excise duty. The list will be kept under periodical review with a view to adding more items as may be warranted;
- Controlled cloth is meant for the weaker sections of society and its cost should be as low as possible. I, therefore, propose to exempt controlled cloth from excise duty;
- Cotton and Cotton-viscose blend hosiery consisting of items like banians are of relatively low value and these are now subject to excise duty at 8 per cent. I propose to exempt them fully from excise duty;
- Cycles are the poor man's conveyance. I, therefore, propose to totally exempt cycles and cycle parts falling under Item 68 from excise duty.

— Sewing machines, which are indispensable to the housewife and also enable the weaker sections to earn a living, will also be fully exempted from excise duty.

— Pressure cookers which take the drudgery out of the house wife's daily tasks and save fuel now attract duty at 15 per cent. I propose to reduce it to 10 per cent.

112. I also propose to make substantial reductions in excise duty on some other items of everyday use. Accordingly —

- Excise duty on cheaper varieties of toilet soap will be reduced from 10 per cent to 5 per cent;
- Excise duty on tooth paste will be reduced from 20 per cent to 10 per cent;
- Vacuum and gas-filled bulb, not exceeding 60 watts will have the duty reduced from 15 per cent to 10 per cent.

113. I am sure these substantial concessions, which would cost the exchequer approximately Rs. 15 crores in a full year, will be welcomed by Parliament and by the public. I also hope that industry and trade will play fair by the consumer and pass on the benefit of these only reductions to the consumer.

114. Our Party's election manifesto has referred to the need to encourage dieselisation of taxis. In fulfilment of this commitment and with a view to giving an incentive for taxi-owners to go in for dieselisation, I propose to extend full excise duty exemption to diesel engines used for conversion of petrol driven taxis.

115. My second proposal is aimed at giving relief to the cycle rickshaw driver. Powered cycle rickshaws are already exempt from excise duty. To encourage motorisation of non-powered cycle rickshaws, I propose to extend full duty exemption for internal Combustion engines used for this purpose. I am sure Hon'ble Members will welcome this measure, as a visible sign of our keenness to reduce physical strain and at the same time encourage this relatively cheap means of transport.

116. Before I leave the field of indirect taxes, I have a major decision of policy to announce. For the past couple of decades, there has been a persistent public demand for the setting up of an independent Appellate Tribunal for customs and central excise matters, somewhat similar to the set-up on the Direct Taxes side. This demand has recently been endorsed by the Estimates Committee of Parliament. Government has, in the past not been in favour of such a system, as it was felt that it would not be appropriate in the case of indirect taxes, and that the present departmental machinery was in fact adopting an objective approach. I think a time has come when we should gracefully accept the common view, which is based on the dictum that justice should not only be done but should also seem to be done. It is in this spirit that provision has been made in the Finance Bill for setting up an Appellate Tribunal to hear appeals in respect of customs, central excise and gold control matters. This Tribunal will be independent of the executive machinery charged with the responsibility of day-to-day administration of revenue laws. I have no doubt that this measure will meet with the whole-hearted approval of Parliament and of trade and industry.

117. My taxation proposals will yield a sum of Rs. 223.22 crores in a full year in central excise duties and Rs. 39.58 crores in customs duties. The reliefs I have announced add up to Rs. 34.75 crores on the central excise side and Rs. 7.93 crores on the customs side. The net yield is, therefore, Rs. 188.47 crores from central excise duties and Rs. 31.65 crores from customs duties. The accrual to the Central exchequer in a full year will be Rs. 144.85 crore, and the share of the States will be Rs. 75.27 crores.

118. Where changes are proposed to be made by notifications, effective from the 19th June, 1980, copies of such notifications will be laid on the Table of the House in due course.

119. I wish to say now a few words on behalf of my honourable colleague, the Minister of Communications. Payment of dearness allowance and sanction of bonus linked to

productivity in the staff of the Posts and Telegraphs Department have increased the working expenses of the Department. It has therefore, become necessary to increase the tariffs on a few selected services. In making tariff revision proposals, Government has carefully avoided revision of charges for such services as are generally used by the common man. There will be no increase in the price of post cards and inland letters. The tariff for letters is, however, being increased from 30 paise to 35 paise at the lowest slab. The rate for parcels will be stepped up from Rs. 1.50 to Rs. 2.00 for every 500 grams. The charges for installation and shifting of telephone connections are also being increased. Local calls beyond 5,000 calls in a quarter will be charged at 50 paise per call as against 40 paise at present. A memorandum showing the proposed tariffs is being circulated along with Budget papers. It will be seen that the charges for the bulk of postal and tele-communications services have been left untouched. The changes would take effect from a date to be notified after the Finance Bill is passed by Parliament. The proposed tariff revisions are estimated to bring in an additional revenue of Rs. 27.10 crores per annum. The additional revenue during the year 1980-81 would be of the order of Rs. 13 crores and has been taken into account in estimating the revenues of the Posts and Telegraphs.

120. The tax effort net of reliefs proposed in the Budget will on the whole bring in about Rs. 282 crores for the current year, of which Rs. 223 crores will accrue to the Centre. There will be a residual deficit of Rs. 1417 crores which I propose to leave uncovered. This deficit is only a little over half the deficit of last year. It is my judgement that a deficit of this order will not have a significantly adverse impact on the economy. If the monsoon turns out to be normal and if we continue the sound economic policies already initiated, there is every hope that there will be an appreciable improvement in agriculture and industrial production resulting in a

significant growth of GNP. We shall also pursue a responsible monetary policy so that expansion of bank credit for unproductive or speculative purposes is held in check.

121. Sir, within the constraints imposed by the difficult economic situation inherited by the present Government, I have endeavoured my best to provide relief to those who deserve it most. But since reliefs can only be palliatives and the real need of a poor society is growth, I have tried to impart a judicious stimulus to investment. With the higher levels of investment, in the public sector as well as the private sector, and its particular sectoral distribution, both production and employment should register a substantial increase. This Government has a special responsibility towards the weaker sections of society who have so enthusiastically supported it. The Budget seeks to protect them through special programmes designed to promote their well being. It is also our firm resolve that no matter how difficult the economic situation is, the minimum basic needs of consumption of the poorer sections and the middle classes will be met through a reinvigorated public distribution system. With a strong and cohesive Government it should be possible to utilise fully the existing production potential.

122. My Budget represents a modest contribution to the process of restoring the country's economy to the path of stability, growth and social justice. Its success, however, depends upon the cooperation of all people who work in the fields or factories, power stations or ports, railways or coal mines. The people of this country have high hopes about the ability of the Present Government to achieve these goals and I am sure will be prepared to give their whole hearted support in this task. It should be the common endeavour of all of us, rising above partisan prejudices and passions to harness the people's enthusiasm for the tasks of development.

A. C. TIWARI, Lt. Secy.

